वर्ष 12 • अंक 256 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शनिवार 14 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

फसलों पर बारिश और ओलों की मार

निर्मला सीतारमण पृष्ठ 4

वादे के मुताबिक हो रहा पूंजीगत व्यय

डॉलर रु. 70.80 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 79.20 ▲ 40 पैसे | सोना (10ग्राम) रु. 37676 ▼ 102 रुपये | सेंसेक्स 41009.70 ▲ 428.00 | निफ्टी 12086.70 ▲ 114.90 | निफ्टी फ्यूचर्स 12142.30 ▲ 55.60 | ब्रेंट क्रूड 66.60 डॉलर ▲ 0.30 डॉलर

एक नज़र

नवंबर में मामूली घटा निर्यात, आयात भी कम

देश से होने वाला निर्यात नवंबर में 0.34 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 25.98 अरब डॉलर रहा। इस दौरान आयात भी घटकर 38.11 अरब डॉलर रह गया। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आलोच्य अवधि में व्यापार घाटा कम होकर 12.12 अरब डॉलर पर आ गया। पिछले साल नवंबर में निर्यात 26.07 अरब डॉलर और आयात 43.66 अरब डॉलर रहा था। नवंबर, 2018 में व्यापार घाटा 17.58 अरब डॉलर रहा था। समीक्षाधीन महीने में कच्चे तेल का आयात 11.06 अरब डॉलर रहा।

टीवी सोमनाथन बने नए व्यय सचिव

अगले वित्त वर्ष का बजट तैयार करने में लगी सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को व्यय सचिव बनाया है। यह पद अक्टूबर से रिक्त था। सरकार ने शुक्रवार को अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किए। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सोमनाथन को व्यय सचिव नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल अपने कैडर राज्य तमिलनाडु में कार्यरत हैं। मंत्रालय के एक अन्य आदेश के अनुसार रवि मित्तल सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त किए गए हैं। वह अमित खरे का स्थान लेंगे।

एनबीएफसी बिगाड़ सकती हैं बैंकों की रेटिंग : मूडीज

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय बैंकों को संकटग्रस्त वित्तीय कंपनियां झटके दे सकती हैं। मुश्किल दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के फंसे कर्ज और खुदरा एवं एसएमई कर्जदारों को ऋण आवंटित करने में इन कंपनियों की लाचारी से बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव बढ़ेगा। पृष्ठ 4

जॉनसन की प्रचंड जीत, ब्रेक्जिट का रास्ता साफ

ब्रिटेन में हुए ऐतिहासिक चुनाव में मतदाताओं ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को प्रचंड जनादेश दिया है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को शुक्रवार को संसद में निर्णायक बहुमत मिला। इससे अब ब्रिटेन के यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। ब्रिटिश संसद के 650 सदस्यीय निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत से 79 सीटें अधिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के कई नेताओं ने जॉनसन को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। पृष्ठ 12

आज का सवाल

क्या बैंकों की तरह सख्त नियम से एनबीएफसी में बढ़ेगी जवाबदेही

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या बॉन्ड में एफपीआई निवेश सीमा बढ़ाना उचित कदम होगा?	हां **42.86%**
	नहीं **57.14%**

एनबीएफसी के नियम होंगे सख्त

बैंकों की तरह सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के लिए सतर्कता नियम पर विचार

सुब्रत पांडा
मुंबई, 13 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफासी) और सहकारी बैंकों के लिए भी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह सख्त नियम-कायदे का अनुपालन सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की आज हुई बैठक में 'प्रवर्तन नीति और प्रारूप' का दायरा बढ़ाने पर विचार किया गया। अभी इसके दायरे में वाणिज्यक बैंक आते हैं लेकिन अब इसमें एनबबीएफसी और सहकारी बैंक भी आएंगे।

इसके तहत एनबीएफसी और सहकारी बैंकों पर भी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही निगरानी मोर्चे पर पहल करनी होगी। वर्तमान में एनबीएफसी और सहकारी बैंकों के संचालन के लिए अलग नियमन हैं, जो बैंकों की तरह सख्त नहीं हैं। केंद्रीय बैंक ने निरीक्षण विभाग नाम से एक नए विभाग का गठन किया है जिसके पास आरबीआई के नियमन दायरे में आने वाली सभी इकाइयों की निगरानी की जिम्मेदारी होगी। आरबीआई ने इस मकसद के लिए एक अलग निगरानी कैडर तैयार किया है।

- आरबीआई प्रवर्तन नीति और प्रारूप का दायरा बढ़ाने पर कर रहा विचार
- बैंकों की तरह करना होगा खुलासा और प्रावधानों का पालन
- लेखा मानकों में चूक के लिए सांविधिक ऑडिटर हो सकते हैं जिम्मेदार

आरबीआई के विनियमन में आने वाली सभी इकाइयों के लिए समान निगरानी नियम लागू होंने और उसके उल्लंघन पर जुर्माना भी एकसमान होगा। ऐसे में अगर 'प्रवर्तन नीति और प्रारूप' के दायरे में एनबीएफसी और सहकारी बैंकों को भी शामिल किया जाता है तो उन्हें संपत्ति श्रेणी में विचलन का खुलासा करना होगा और अपने अंकेक्षित वित्तीय विवरण में उसके लिए प्रावधान करना होगा। अभी तक एनबीएफसी और सहकारी बैंकों को इस तरह के खुलासे और प्रावधान से छूट मिलती रही है।

देश में 98,000 से अधिक सहकारी बैंक और 10,000 से अधिक एनबीएफसी हैं। ऐसे में आरबीआई मुख्य रूप से शीर्ष 50 सहकारी बैंकों और एनबीएफसी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों की संख्या केपल 54 हैं, वहीं केंद्रीय बैंक पहले से ही रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण 50 प्रमुख एनबीएफसी की निगरानी कर रहा है। अगर आरबीआई इस दिशा में आगे बढ़ता है और नया अनुपालन ढांचा को अनिवार्य बनाता है तो इन इकाइयों की दैनिक आधार पर जांच करना उसके लिए काफी कठिन होगा।

वर्ष 2017 में आरबीआई ने कहा था कि बैंकों को उसके बारे में समुचित खुलासा करना होगा अगर केंद्रीय बैंक के आकलन में अतिरिक्त प्रावधान करने की जरूरत संबंधित बैंक के कर बाद शुद्ध मुनाफे से 15 फीसदी अधिक हो। इसके अलावा एनबीएफसी और सहकारी बैंकों के सांविधिक ऑडिटरों की ओर से किसी तरह की गड़बड़ी होती है और ऋणदाता की वित्तीय स्थिति की सही तस्वीर सामने नहीं लाई जाती है तो इसके लिए ऑडिटरों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बैंकों के लिए पहले से ही इस तरह के नियम लागू हैं।

आईएलऐंडएफएस और पंजाब ऐंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक के धराशायी होने से सांविधिक ऑडिटरों द्वारा की जाने वाले ऑडिट की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के हालिया मूल्यांकन में पाया गया कि डेलॉयट हसकिंस ऐंड सेल्स अकाउंटिंग के मानकों का अनुपालन करने में विफल रही और आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज के मामले में अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता किया और मोटी शुल्क पर प्रतिबंधित गैर-ऑडिटिंग सेवाएं मुहैया कराई।

असम समेत पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था पर चोट

डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में ढील के बाद पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर में हिंसक विरोध के कारण कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। पीटीआई

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

- इलाके की रिफाइनरियों, रासायनिक एवं उर्वरक उद्योगों को आपूर्ति भी अशांति से हो रही प्रभावित
- तेल एवं गैस उत्पादन 4 दिन से ठप
- आपूर्ति प्रभावित होने से कई आवश्यक चीजों के बढ़े दाम
- प्याज के दाम 200 रुपये किलो तक पहुंचे

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पारित होने के बाद असम में शुरू हुए प्रदर्शनों से अब पूर्वोत्तर राज्यों की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती खड़ी होती दिख रही है। तेल एवं उत्पादक क्षेत्रों में चार दिनों से उत्पादन ठप पड़ा हुआ है, चारों रिफाइनरी में काम बाधित हो गया है और रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा थोक बाजारों के बंद होने से पूरे इलाके में जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने की भी आशंका पैदा हो गई है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल उत्पादक क्षेत्रों में गत चार दिनों से उत्पादन ठप पड़ा हुआ है और असम गैस कंपनी का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी (एनआरएल) को यूरो-6 मानकों के अनुरूप उन्नत करने का काम भी प्रभावित हुआ है। असम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि थोक बिक्री बाजारों के बंद होने से प्रतिदिन हो रही क्षति समूचे पूर्वोत्तर भारत की जीवनरेखा को प्रभावित कर रही है। विभिन्न खाद्य एवं अन्य आवश्यक उत्पादों की कीमतें भी बढ़ गई हैं।

ऑयल इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि गत चार दिनों से प्रदर्शनों का सिलसिला जारी होने से तेल-क्षेत्र बंद पड़े हुए हैं। इससे करीब 5,000 किलोलीटर तेल उत्पादन कम हुआ है जो करीब 8-10 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति है। ऑयल इंडिया को किराये पर लिए गए ड्रिलिंग उपकरणों के निष्क्रिय पड़े रहने से भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि इस गतिरोध के बाद उत्पादन के दोबारा शुरू होने पर भी तेल-क्षेत्रों का अधिकतम उत्पादन हासिल कर पाना मुश्किल होगा।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 7,000 से अधिक लोगों ने ऑयल इंडिया के इंडस्ट्रियल एरिया गेट के सामने प्रदर्शन किया जिससे वहां काम ठप हो गया। तेल-गैस कंपनी ओएनजीसी का भी कामकाज प्रभावित हुआ है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में जारी प्रदर्शनों की वजह से ओएनजीसी का परिचालन रोकना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक ऊर्जा क्षेत्र की ये दोनों सरकारी कंपनियां पूर्वोत्तर भारत में सालाना करीब 43 लाख टन कच्चे तेल और 3.2 अरब घन मीटर गैस का संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। नागरिकता प्रावधानों में बदलाव करने वाले कानून का विरोध तेज होने से पूर्वोत्तर में मौजूद रिफाइनरियों और रासायनिक एवं उर्वरक उद्योगों को होने वाली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार रिफाइनरी हैं जिनमें से तीन इंडियन ऑयल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की है। गत वित्त वर्ष में चारों रिफाइनरी ने मिलकर करीब 70 लाख टन कच्चे तेल का शोधन किया था।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

वैश्विक बाजार की ताल पर झूमा सेंसेक्स

सुंदर सेतुरमण
मुंबई,13 दिसंबर

भारतीय शेयर सूचकांक भी शुक्रवार को वैश्विक बाजार की ताल पर झूम उठे। अमेरिका और चीन के एक सीमित व्यापार समझौते की तरफ बढ़ने और मौजूदा शुल्कों में कटौती की खबरों से निवेशकों ने जमकर लिवाली की। ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी के नेता एवं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ऐतिहासिक जीत के बाद ज्यादातर यूरोपीय बाजारों में तेजी देखी गई।

शुक्रवार को सेंसेक्स 428 अंक उछलकर 41,010 पर बंद हुआ। पिछले दो हफ्तों का यह सबसे ऊंचा स्तर है। निफ्टी में भी 114 अंक चढ़कर 12,087 पर बंद हुआ। जानकारों का मानना है कि चीन के 360 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं पर शुल्क वापस लेने की अमेरिका के प्रस्ताव के बाद बाजार का उत्साह बढ़ गया। अमेरिका ने मार्च 2018 में इन वस्तुओं पर शुल्क लगाया था।

बाजार पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि हाल में वैश्विक स्तर पर हुए घटनाक्रम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक सुस्ती बनी रहने की आशंका कम हो गई है।

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेस के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजय कुमार कहते हैं, 'अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को लेकर सहमति बनने से तमाम उतार-चढ़ावों के बाद आया है और इसे एक नई सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है।' पिछले तीन कारोबारी सत्रों में बेंचमार्क सूचकांक में 2 प्रतिशत से अधिक तेजी आई है।

अब अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने पर मोदी सरकार का ध्यान

अरूप रायचौधरी और संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

- आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होंगी कई बैठकें
- 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों एवं सलाहकारों के साथ लेंगे स्थिति का जायजा

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने और नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पारित कराने के बाद सरकार अब सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में कई बैठकें होने वाली हैं। 19 दिसंबर को नीति आयोग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेगा। इसी तरह, 20 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम बजट पूर्व चर्चाओं के लिए विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगी। 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों एव सलाहकारों के साथ स्थिति का जायजा लेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड को शीर्ष सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन बैठकों में चर्चा के बाद निकले उपाय वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में जगह पा सकते हैं। पिछले बजट में पेश कई प्रस्ताव वापस लिए जाने के बाद इस बार प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का जोर ऐसी किसी पुनरावृत्ति से बचने पर होगा।

सूत्रों ने कहा कि इन निर्धारित बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) मौजूदा विभिन्न योजनाओं, उनके प्रदर्शन और इन्हें और बेहतर बनाने के उपायों पर शीर्ष सचिवों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने कहा कि कुछ बैठकों में सब्सिडी तर्कसंगत बनाने, आयुष्मान भारत का डिजिटल प्रसार बढ़ाने, स्वच्छ भारत अभियान को अधिक प्रभावी बनाने और दूसरी कई मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

महंगे मोबाइल की तस्करी से खजाने को चपत

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

- **50,000** रुपये से अधिक दाम वाले मोबाइल फोनों का सालाना कारोबार **15,000** करोड़ रुपये
- वैध बिल के जरिये **7,500** से **8,000** करोड़ रुपये मूल्य की होती है बिक्री
- ग्रे बाजार में **8,000** करोड़ रुपये का कारोबार
- राजस्व को नुकसान करीब **2,400** करोड़ रुपये

50,000 रुपये से अधिक कीमत में बिकने वाले करीब आधे मोबाइल फोन तस्करी के जरिये देश में लाए जा रहे हैं, जिससे सरकार के खजाने को चपत लग रही है। इस खंड में ऐपल आईफोन, दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग और गूगल पिक्सल के कुछ मॉडल शामिल हैं।

मोबाइल उपकरण कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भारतीय सेल्युलर एवं इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को सौंपे गए डेटा के अनुसार इस 15,000 करोड़ रुपये के सेगमेंट में करीब 8,000 करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन देश में ग्रे मार्केट के जरिये आ रहे हैं। देश में बिकने वाले कुल मोबाइल फोन में इस सेगमेंट की हिस्सेदारी करीब 7.2 फीसदी है। मोबाइल की तस्करी की वजह से सरकार को वस्तु एवं सेवा कर के साथ ही बुनियादी सीमा शुल्क मद में सालाना 2,400 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

मोबाइल फोन की तस्करी की वजह साफ है। सरकार ने ऐसे फोन पर 20 फीसदी सीमा शुल्क लगाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना है। लेकिन यह रणनीति कारगर होती नहीं दिख रही है। उच्च कराधान के कारण कानूनी रास्ते से देश में आयात होने वाले मोबाइल फोनों और ग्रे मार्केट के जरिये आने वाले फोनों की कीमत में काफी अंतर होता है और अच्छी कमाई का अवसर मिलता है। यही वजह है कि दुबई और हॉन्ग कॉन्ग जैसे देशों से मोबाइल फोनों को भारत लाया जाता है।

संक्षेप में

रिलायंस की इकाई ने खरीदी हिस्सेदारी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स (आरएसबीवीएल) ने एस्टेरिया एरोस्पेस में 51.78 फीसदी हिस्सेदारी का 23.12 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में कहा है कि आरएसबीवीएल ने एस्टेरिया एरोस्पेस के शेयरों का 23,12,49,584 रुपये नकद में अधिग्रहण किया है। यह एस्टेरिया की इक्विटी शेयर पूंजी का 51.78 फीसदी है। कंपनी ने कहा कि इस निवेश से समूह की उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पहल और मजबूत हो सकेगी। यदि एस्टेरिया की सहमति वाले लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो आरएसबीवीएल उसमें 125 करोड़ रुपये का और निवेश करेगी। इसके दिसंबर 2021 तक पूरा होने का उम्मीद है। *भाषा*

इन्फोसिस की इकाई का आईडेगो संग करार

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस की सहायक इकाई एजवर्व ने लैटिन अमेरिका में उपभोक्ताओं के लिए प्रौद्योगिकी उत्पाद विकसित करने के लिए डिजिटल बदलाव को लेकर परामर्श देने वाली कंपनी आइडेगो के साथ करार किया है। इंफोसिस ने एक बयान में बताया कि इस साझेदारी से दूरसंचार तथा वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों को उत्पादकता एवं दक्षता बढ़ाने में मदद मुहैया कराई जाएगी। इंफोसिस ने कहा कि एजवर्व उन्नत कृत्रिम मेधा क्षमताओं से लैस है और स्वचालन का मंच मुहैया कराती है। *भाषा*

टेलीनॉर ने 5जी निविदा से हुआवेई को दूर किया

नॉर्वे की दूरसंचार कंपनी टेलीनॉर ने शुक्रवार को कहा कि उसने 5जी नेटवर्क के उपकरणों के लिए चीन की हुआवेई की जगह स्वीडन की एरिक्सन को चुना है। टेलीनॉर ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने हुआवेई के चीन की सरकार के साथ मिले होने की चेतावनी जारी की है। यह अमेरिका के उस आह्वान के अनुकूल है, जिसमें अमेरिका के सहयोगी देशों से 5जी नेटवर्क में हुआवेई को किसी भी तरह की भागीदारी नहीं देने का सुझाव दिया गया है। उल्लेखनीय है कि हुआवेई ने टेलीनॉर को 4जी नेटवर्क के लिए उपकरणों की आपूर्ति की है। *एजेंसियां*

जीआईसी ने निपटाया भेदिया कारोबार का मामला

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) ने 1.23 करोड़ रुपये के शुल्क का भुगतान कर भेदिया कारोबार के उल्लंघन के एक मामले को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ सुलटा लिया है। सेबी ने ऐक्सिस बैंक की हिस्सेदारी के मामले में गहन जांच की। जांच में पता चला कि जीआईसी ने ऐक्सिस बैंक में हिस्सेदारी में बदलाव के संबंध में जानकारी देने में देरी की। भेदिया कारोबार रोधी प्रावधानों के तहत ऐसी जानकारियां मुहैया कराना आवश्यक है। हालांकि सेबी ने मामले को आगे बढ़ाने तथा कार्रवाई शुरू करने से पहले जीआईसी को अक्टूबर 2019 में मामला सुलटाने के संबंध में नोटिस दिया। सेबी ने नोटिस में बताया कि यदि मामला सुलटाने का आवेदन तथा 1.23 करोड़ रुपए के शुल्क का भुगतान किया जाए तो इसे समाप्त किया जा सकता है। जीआईसी ने इसके उत्तर में सुलटाने का आवेदन दायर किया था। *भाषा*

भारतीय विमानन कंपनियों को होगा बड़ा घाटा

एविएशन कंसल्टेंसी कापा की रिपोर्ट, भारतीय विमानन कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में होगा 60 करोड़ डॉलर का नुकसान

अनीश फडणीस
मुंबई, 13 दिसंबर

भारतीय विमानन कंपनियां मौजूदा वित्त वर्ष में संयुक्त रूप से 60 करोड़ डॉलर का नुकसान दर्ज करेंगी और अपने बेड़े में कम विमान शामिल कर पाएंगी। एविएशन कंसल्टेंसी कापा ने ताजा रिपोर्ट में ये बातें कही है।

कापा ने जून में भारतीय विमानन कंपनियों का सालाना लाभ 50-70 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे संशोधित 60 करोड़ डॉलर नुकसान का अनुमान जताया है, जिसकी वजह बाजार की अग्रणी इंडिगो और स्पाइसजेट के कमजोर नतीजे हैं। इंडिगो ने दूसरी तिमाही में 1,062 करोड़ रुपये का नुकसान और स्पाइसजेट ने 462 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया है।

कीमतों पर युद्ध के साथ आक्रामक विस्तार और रखरखाव खर्च में बढ़ोतरी ने भी विमानन कंपनियों के नकदी प्रवाह पर असर डाला है। कापा ने कहा, इंडिगो को छोड़ दें तो ज्यादातर विमानन कंपनियां जोखिम के दायरे में हैं और कुछ मामलों में उपलब्ध नकद शेष कुछ दिन या कुछ हफ्ते का खर्च पूरा कर पाएंगे।

कापा को लग रहा है कि लेखा नियमों में बदलाव व विमानों के रखरखाव पर प्रावधान बढ़ने से इंडिगो का सालाना लाभ 7 से 9 करोड़ डॉलर रहेगा जबकि जून में 40-50 करोड़ डॉलर की आय का अनुमान जताया था। कंसल्टेंसी ने कहा है, स्पाइसजेट लगातार दूसरे साल नुकसान दर्ज कर सकता है और कंपनी ने 2015 के बाद सबसे कमजोर नतीजे घोषित किए हैं। गोएयर 2.5-3 करोड़ डॉलर का मुनाफा दर्ज कर सकती है, वहीं एयरएशिया इंडिया, विस्तारा और एयर इंडिया नुकसान दर्ज करेगी। कापा के अनुमान के मुताबिक, एयर इंडिया मौजूदा वित्त वर्ष में 50 करोड़ डॉलर का नुकसान दर्ज करेगी, जिसकी वजह 20 विमान खड़ा होना और जेट एयरवेज के बंद होने के बाद उपलब्ध मौके का फायदा उठाने में अक्षमता है।

कापा ने कहा, जेट के बंद होने और ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहने की पृष्ठभूमि में एकीकरण के संभावित फायदे और क्षमता को व्यावहारिक बनाने का काम मोटे तौर पर नहीं किया गया। जेट की तरफ से खाली स्लॉट पर कब्जा करने की खातिर विमानन कंपनियों ने आक्रामक विस्तार की प्रक्रिया शुरू की, जिसके कारण प्रतिफल पर असर पड़ा।

नवंबर में देसी हवाई परिवहन में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो कैलेंडर वर्ष 2020 में दो अंकों में बढ़ोतरी दर्ज करने वाला पहला महीना है। इसकी वजह कम किराया और जेट एयरवेज के बंद होने के बाद गंवाई की क्षमता की रिकवरी है। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि छूट पर टिकटों की बिक्री और त्योहारी सीजन में कम किराये पर भारी अग्रिम बिक्री वजह से नवंबर में यात्रियों की संख्या बढ़ी है।

नवंबर में यात्री संख्या में माह दर माह आधार पर 3.86 फीसदी और सालाना आधार पर 11.2 फीसदी बढ़ोतरी रही। नवंबर में करीब 1.2 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी, जो अक्टूबर में 1.1 करोड़ थी। हालांकि कम किराये की वजह से हो रही इस अलाभकारी वृद्धि के आगे भी बने रहने को लेकर उद्योग की राय बंटी हुई है। कुछ का कहना है कि यह आर्थिक मंदी को मात देने की हवाई यात्रा की क्षमता को दर्शाता है।

देसी विमानन कंपनियों ने नवंबर में कुल 628 विमानों का परिचालन किया, जो जनवरी में 614 था। हालांकि एयरबस ए 320 नियो इंजन और बोइंग 737 विमान पर पाबंदी के नियामकीय आदेश से जुड़ी चुनौतियों के कारण नई क्षमता नहीं जोड़ी जा सकी। जून में कापा ने अनुमान लगाया था कि साल के आखिर में विमानन कंपनियों के बेड़े का संयुक्त आकार 709 से 726 विमान होगा, लेकिन अब उसने बेड़े में कुल 710-717 विमान रहने का अनुमान जताया है। गोएयर, एयरएशिया और स्पाइसजेट पहले के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले कुछ ही विमान बेड़े में शामिल करेंगी।

विमानन उद्योग की बढ़ेगी चिंता

- **इंडिगो ने दूसरी तिमाही में 1,062 करोड़ रुपये का नुकसान और स्पाइसजेट ने 462 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया है**
- **कीमत युद्ध के साथ आक्रामक विस्तार और रखरखाव खर्च में बढ़ोतरी ने भी विमानन कंपनियों के नकदी प्रवाह पर असर**

स्पाइसजेट ने तीन बोइंग 737 को बाहर किया

निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने शुक्रवार को कहा कि उसने तीन बोइंग 737 मालवाहक विमानों को उड़ान से बाहर कर दिया है। कंपनी ने बीएसई को बताया कि उसने इजराइली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सलाह पर अमल करते हुए यह कदम उठाया है।

इजराइली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने ही इन विमानों को मालवाहक विमानों में तब्दील किया है। स्पाइसजेट ने कहा कि इजराइली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की आंतरिक जांच में इन विमानों में लगाए गए 9जी रिजिड बैरियर के विनिर्माण की प्रक्रिया में संभावित खामी का पता चला है। कंपनी ने कहा कि नियामकीय मंजूरियों के बाद ये विमान सेवा में लौट जाएंगे। *भाषा*

अमेरिका में डॉ रेड्डीज से पहले एमनियल को मंजूरी

सोहिनी दास
मुंबई, 13 दिसंबर

सीमित प्रतिस्पर्धा वाली एक प्रमुख दवा के लिए अमेरिकी औषधि नियामक यूएसएफडीए से मंजूरी हासिल करने में अमेरिकी दवा कंपनी एमनियल फार्मास्युटिकल्स ने हैदराबाद की दवा कंपनी डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज को पछाड़ दिया है। डॉ रेड्डीज फिलहाल उस दवा पर काम कर रही है। डॉ रेड्डीज का शेयर आज दिन भर के कारोबार के दौरान अधिकतम 3.3 फीसदी की गिरावट के बाद 2.7 फीसदी फिसलकर 2,827 रुपये पर बंद हुआ।

दो भारतीय अमेरिकी बंधुओं द्वारा प्रवर्तित एमनियल फार्मा को जेनेरिक नुवारिंग के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिल गई है। इस दवा का इस्तेमाल गर्भाधान रोकने के लिए किया जाता है। मर्क की दवा नुवारिंग के बाजार का अनुमानित आकार करीब 88 करोड़ डॉलर है और उसमें एकल अंक में वृद्धि हो रही है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस दवा का बाजार 95 करोड़ डॉलर से अधिक है। एमनियल की एलुरिंग सीमित प्रतिस्पर्धा वाली इस दवा का पहला जेनेरिक संस्करण है। कंपनी इस दवा को इसी महीने बाजार में उतारने की योजना बना रही है।

एमनियल की इस दवा के लिए बाजार में महीनों तक काफी सीमित प्रतिस्पर्धा रहेगी। हालांकि कई कंपनियां इसे बाजार में उतारने के लिए तैयारी कर रही हैं। डॉ रेड्डीज के अलावा टेवा फार्मा और मेने फार्मा भी इस दवा की दौड़ में शामिल हैं।

अगस्त में डॉ रेड्डीज को इस दवा के लिए अमेरिकी औषधि नियामक से जवाब (कंप्लीट रिस्पांस लेटर यानी सीआरएल) मिला था। सीआरएल उस सूरत में जारी किया जाता है जब यूएसएफडीए मौजूदा स्वरूप में विपणन के लिए किसी नई अथवा जेनेरिक दवा आवेदन को मंजूरी न देने का निर्णय लेता है। डॉ रेड्डीज को इस मामले में यूएसएफडीए को जवाब देना अभी बाकी है।

> जेनेरिक नूवारिंग के लिए एमनियल को मिली मंजूरी, डॉ रेड्डीज इसे करीब एक साल बाद उतार सकती है

एडलवाइस के दीपक मलिक ने कहा कि उनके आकलन के अनुसार डॉ रेड्डीज वित्त वर्ष 2021 में जेनेरिक नुवारिंग को लॉन्च करेगी वशर्ते कंपनी अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सीआरएल का जवाब दे दे और उसके अगले छह महीने में मंजूरी हासिल कर ले। इस प्रकार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही से पहले इसे बाजार में उतारना डॉ रेड्डीज के लिए संभव नहीं होगा। ऐसे में एमनियल करीब एक साल तक बिना किसी प्रतिस्पर्धा के इस दवा की बिक्री कर सकती है।

नुवारिंग सीमित प्रतिस्पर्धा वाली दवा होने के कारण डॉ रेड्डीज के अमेरिकी कारोबार के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। इसमें बेहतर मार्जिन होने से कंपनी की वृद्धि को बल मिलेगा। विश्लेषकों का कहना है कि एमनियल को उम्मीद से काफी पहले मंजूरी मिल गई है जिससे स्थिति बदल गई है।

मूल्य वृद्धि के डर, छूट से बिकेंगी ज्यादा गाड़ी

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 13 दिसंबर

- **कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कार कंपनियों ने बीएस4 वाहनों की इन्वेंटरी को खपाने के लिए बिक्री रणनीति के तौर पर कीमत वृद्धि की घोषणा की है**
- **कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि यात्री कारों की बिक्री में 2 से 4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है**
- **इस बार औसत मूल्य वृद्धि थोड़ी अधिक होगी क्योंकि कंपनियों को बीएस6 उत्सर्जन मानदंड लागू होने के कारण बढ़ी हुई लागत की भरपाई करनी है**

वाहन कंपनियों ने इनपुट लागत में वृद्धि के बावजूद कार और दोपहिया वाहनों के दाम जनवरी 2020 से बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे दिसंबर में यात्री वाहनों की बिक्री में 2 से 4 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद है। डीलरों का कहना है कि इसके अलावा छूट एवं अन्य योजनाओं की भी पेशकश की जा रही है जिससे खरीदारी के लिए ग्राहकों को सामने आना चाहिए।

जिन कंपनियों ने जनवरी से कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है उनमें मारुति सुजूकी, हुंडई, निसान और बीएमडब्ल्यू शामिल हैं।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष आशिष हर्षराज काले ने कहा कि अभी यह आकलन करना आसान नहीं है कि इस महीने बिक्री में कितनी वृद्धि होगी लेकिन विश्लेषकों, कार कंपनियों और डीलरों ने उम्मीद जताई है कि यात्री कारों की बिक्री में उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि होगी।

कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि यात्री कारों की बिक्री में 2 से 4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। मारुति सुजूकी के कार्यकारी निदेशक (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, 'जाहिर तौर पर यह संभव है। हालांकि उसके लिए कोई आंकड़ा बताना काफी कठिन है। कुछ ग्राहकों ने अपना मन बदल लिया और इससे बिक्री को नवंबर के बजाय दिसंबर में रफ्तार मिली। हम सकारात्मक मांग के लिए काफी सतर्क और आशान्वित हैं।'

श्रीवास्तव ने कहा कि अभी जो छूट दी जा रही है वह सबसे अधिक है और वह अधिक समय तक बरकरार नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, 'इसलिए हम अपने ग्राहकों को बताना चाहते हैं कि कार खरीदने के लिए अभी सबसे अच्छा समय है।'

रिलायंस सिक्योरिटीज के वाहन विश्लेषक मितुल शाह का मानना है कि कार कंपनियों ने बीएस4 इन्वेंटरी को खपाने के लिए बिक्री रणनीति के तौर पर कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घोषणा से निश्चित तौर पर खरीदार जल्द निर्णय लेंगे और बिक्री को रफ्तार मिलेगी।

कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यापक श्रेणियों में मूल्य वृद्धि की घोषणा की गई है। शाह के अनुसार, सामान्य तौर पर हर साल जनवरी में 1 फीसदी की कीमत वृद्धि होती है। लेकिन इस बार औसत मूल्य वृद्धि थोड़ी अधिक होगी क्योंकि कंपनियों को बीएस6 उत्सर्जन मानदंड लागू होने के कारण बढ़ी हुई लागत की भरपाई करनी है। गौरतलब है कि जनवरी में कीमत वृद्धि के बाद बीएस6 वाहनों की बिक्री के लिए अप्रैल 2020 से पहले दोबारा वाहनों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं।

कीमतों में वृद्धि की घोषणा सबसे पहले देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजूकी ने की थी। हालांकि उसने कहा था कि जनवरी से उसके वाहनों के दाम बढ़ जाएंगे लेकिन यह नहीं बताया था कि कितनी वृद्धि होगी। हुंडई ने भी यह खुलासा नहीं किया कि मूल्य वृद्धि कितनी होगी।

निसान, जर्मनी की लक्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज और देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने भी कीमत में वृद्धि की घोषणा की है। निसान और डैटसन इंडिया ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में 5 फीसदी मूल्य वृद्धि (डैटसन रेडिगो के लिए 14,000 रुपये और निसान किक्स के लिए 68,000 करोड़ रुपये) की घोषणा की है। मर्सिडीज बेंज ने कहा है कि उसने विभिन्न मॉडलों के दाम 3 फीसदी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

एयरटेल डीटीएच के डिश टीवी संग विलय के मायने

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

डिश टीवी के साथ भारती एयरटेल के डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) कारोबार के विलय की घोषणा जल्द होने वाली है। इससे इस दूरसंचार कंपनी को होम ब्रॉडबैंड एवं मनोरंजन क्षेत्र में अपनी प्रमुख प्रतिस्पर्धी रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए एक दमदार प्लेटफॉर्म हासिल होगा।

दोनों कंपनियों के बीच यदि विलय होता है तो एकीकृत कंपनी के पास 6.89 करोड़ डीटीएच ग्राहकों में करीब 54 फीसदी हिस्सेदारी होगी। ऐसे में वह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्काई को काफी पीछे छोड़ देगी। टाटा स्काई की बाजार हिस्सेदारी 32 फीसदी है।

यह पहल ऐसे समय में की गई है जब जियो केबल क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रही है। हैथवे और डेन नेटवर्क्स के अधिग्रहण के बाद जियो की पहुंच 20 करोड़ टीवी घरों में से करीब 2.3 करोड़ घरों तक हो जाएगी जो करीब 12 फीसदी है। भारती की नजर भी उसी बाजार तक पहुंच बनाने पर है।

केबल कंपनियों के करीब 20 लाख ग्राहक ब्रॉडबैंड को अपना रहे हैं और ऐसे में जियो को केबल नेटवर्क को फाइबर से बदलने और उन ग्राहकों को फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) सेवाओं की पेशकश करने में एक अवसर दिख रहा है। एफटीटीएच सेवाओं में हाईस्पीड इंटरनेट, ओटीटी (ओवर द टॉप) सेवा के साथ-साथ टीवी भी शामिल हैं। जियो खुद अपने बल पर ओटीटी और ब्रॉडबैंड के साथ एफटीटीएच सेवाएं शुरू कर रही है। उसकी नजर पहले चरण में 2 करोड़ घरों तक पहुंच बनाने पर है।

हालांकि एयरटेल की रणनीति अलग है। जियो (उसके पास कोई डीटीएच कंपनी नहीं है) के विपरीत एयरटेल डीटीएच पर बड़ा दांव लगा रही है। इसके लिए उसने दोहरी रणनीति बनाई है और सावधानीपूर्वक अपनी एफटीटीएच पेशकश में भी विस्तार कर रही है।

डिश टीवी के साथ विलय होने पर एयरटेल की पहुंच काफी नए घरों तक सुनिश्चित होगी। विश्लेषकों का कहना है कि डिजिटल केबल की पहुंच अभी भी करीब 40 फीसदी भारतीय टीवी परिवारों तक है। जबकि डीटीएच की पहुंच तेजी से बढ़ रही है और उसकी बाजार हिस्सेदारी करीब 34 फीसदी (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के शुल्क संबंधी आदेश के बाद कुछ ग्राहक घटे हैं) है।

निश्चित तौर पर एयरटेल का मानना है कि उसकी स्थिति बेहतर है। एयरटेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घरों तक पहुंच बनाने के लिए डीटीएच सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। जबकि फाइबर के मामले में अंतिम उपभोक्ता के लिए लागत और समय दोनों ही अधिक हैं। साथ ही यह पूरे देश में पहुंच सकती है जबकि केबल और फाइबर के मामले में ऐसा नहीं है। खासकर डिश टीवी की यह एक बड़ी ताकत है।

एयरटेल का मानना है कि दो अलग तरह के बाजार हैं जिन्हें भिन्न समाधान की जरूरत है। डीटीएच उनके ग्राहकों के लिए उपयुक्त है जो 200 से 300 रुपये प्रति महीने से अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं। जबकि फाइबर टु होम उन ग्राहकों के लिए अधिक उपयुक्त है जो 700 रुपये प्रति महीने से अधिक खर्च कर ओटीटी, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आदि के जरिये मनोरंजन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसका बाजार ऊपरी तबके का है।

अनुमानों के अनुसार, एफटीटीएच बाजार का आकार करीब 3 करोड़ परिवारों का है जिनकी वार्षिक आय करीब 10 लाख रुपये है। विश्लेषकों का कहना है कि इस आय वर्ग के लोग एफटीटीएच को वहन कर सकते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों को दूर कर दिया जाए तो इस बाजार का आकार महज करीब 2 करोड़ ग्राहकों का होगा।

इससे साफ पता चलता है कि जियो ने एफटीटीएच के लिए शुरुआती लक्ष्य छोटा क्यों रखा है। भारती पिछले कई वर्षों से फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की पेशकश कर रही है लेकिन उसकी पहुंच महज 23.6 लाख घरों तक ही हो पाई है। जबकि अगले तीन साल में वह 50 लाख नए घरों तक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है।

भारती एयरटेल उन ग्राहकों को अपनी तमाम सेवाओं की पेशकश एक साथ करने में भी संभावनाएं देख रही है जो भुगतान करना चाहते हैं। इसलिए उसने तीन एकीकृत सेवाओं के लिए योजना बना रही है जिसमें डीटीएच, ब्रॉडबैंड, ओटीटी और मोबाइल कनेक्शन एक ही पैकेज और एक ही बिल के तहत दिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी एक एकीकृत बॉक्स लाने के लिए भी काम कर रही है जिसके जरिये इन सभी सेवाओं की एक साथ पेशकश उपलब्ध होगी।

डीटीएच का बाजार

जून 2019 तिमाही के सक्रिय ग्राहकों में किसकी कितनी हिस्सेदारी

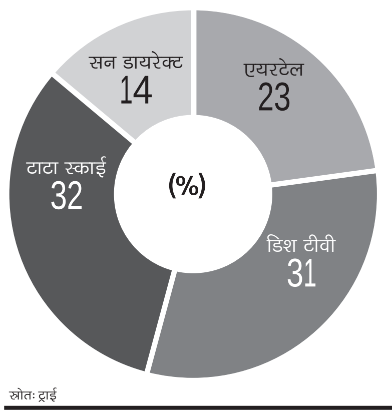

स्रोतः ट्राई

अगले हफ्ते आर्सेलर की होगी एस्सार

ईशिता आयान दत्त
और नम्रता आचार्य
कोलकाता/हैदराबाद, 13 दिसंबर

एस्सार स्टील का दिवालिया समाधान

- दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता आर्सेलरमित्तल के लिए भुगतान की एक महीने की समयसीमा सोमवार को समाप्त हो रही है
- लेनदार और सूत्रों ने कहा कि भुगतान जल्द से जल्द हो सकता है
- एस्सार स्टील का स्वामित्व अब आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के पास होगा और दोनों मिलकर इसका परिचालन करेंगी
- करार के मुताबिक, आर्सेलर के पास इस उद्यम की 60 फीसदी हिस्सेदारी होगी जबकि बाकी निप्पॉन स्टील के पास होगी
- दोनों कंपनियों का निदेशक मंडल में समान प्रतिनिधित्व होगा और मतदान का अधिकार भी समान होगा

आर्सेलरमित्तल अगले हफ्ते एस्सार स्टील के लेनदारों के साथ 42,000 करोड़ रुपये का लेनदेन पूरा कर सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता के लिए भुगतान की एक महीने की समयसीमा सोमवार को समाप्त हो रही है। लेनदार और सूत्रों ने कहा कि भुगतान जल्द से जल्द हो सकता है।

सूत्र ने कहा, आंतरिक लक्ष्य सोमवार तक का है और दो अग्रणी लेनदारों ने पुष्टि की है कि यह काम सोमवार तक पूरा हो सकता है। आर्सेलरमित्तल ने इस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन पिछले महीने एक बयान में कहा था कि उन्हें यह सौदा साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। एक लेनदार ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का एक महीना सोमवार को पूरा होगा।

एस्सार स्टील के अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) के दस्तावेज के मुताबिक, मंजूरी आदेश के एक महीने के भीतर भुगतान करना होगा या फिर समाधान वाली रकम पर सीमांत लागत वाली उधारी दर के हिसाब से ब्याज लगाया जाएगा।

15 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीएलएटी के आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसने अलग-अलग लेनदारों की श्रेणी (वित्तीय व परिचालक) को एकसमान माना था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने आर्सेलरमित्तल के लिए समाधान योजना लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

बुधवार को आखिरी अवरोध भी सरकार ने दूर कर दिया क्योंकि उसने दिवालिया संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों में कॉरपोरेट कर्जदार को पहले के प्रबंधन या प्रवर्तकों की गलतियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही से छूट दिया जाना शामिल है। मित्तल ने एस्सार स्टील की पिछली आपराधिक देनदारी से छूट मांगी थी।

एस्सार स्टील का स्वामित्व अब आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के पास होगा और दोनों मिलकर इसका परिचालन करेंगी। निप्पॉन स्टील जापान की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है।

दोनों कंपनियों के बीच हुए करार के मुताबिक, आर्सेलर के पास इस उद्यम की 60 फीसदी हिस्सेदारी होगी जबकि बाकी निप्पॉन स्टील के पास होगी। दोनों कंपनियों का निदेशक मंडल में समान प्रतिनिधित्व होगा और मतदान का अधिकार भी समान होगा।

सौदा पूरा होने के बाद 800 दिन तक चली कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। एस्सार को एनसीएलटी में 2 अगस्त 2017 को भेजा गया था। दिवालिया संहिता के तहत समाधान के लिए आरबीआई की 12 कंपनियों की सूची में एक एस्सार थी। एस्सार के ऊपर लेनदारों का करीब 49,000 करोड़ रुपये बकाया है। एस्सार स्टील पर सबसे ज्यादा बकाया भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का रहा है और यह रकम 13,226 करोड़ रुपये है। बैंक ने एस्सार स्टील के लिए 100 फीसदी प्रावधान किया है और एस्सार से मिलने वाली रकम बैंक के लाभ-हानि खाते में शामिल होगी।

एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक ने जुटाए 525 करोड़ रुपये

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

सिंगापुर के सॉवरिन वेल्थ फंड टेमासेक होल्डिंग्स ने अपनी सहायक केम्स इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड के जरिए एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक में 525 करोड़ रुपये निवेश किया है, जो वॉरंट को परिवर्तित करने के जरिये बैंक में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

इस निवेश के जरिये टेमासेक की हिस्सेदारी जयपुर के स्मॉल फाइनैंस बैंक में 4.8 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी होगी। इस निवेश से कंपनी का नेटवर्थ मजबूत होकर 4,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

500 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात और प्रमुख टियर-1 पूंजी में इजाफा करेगा। 30 सितंबर को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 19.7 फीसदी था और प्रमुख टियर-1 पूंजी 16.7 फीसदी।

बैंक ने कहा है कि नेटवर्थ और पूंजी पर्याप्तता अनुपात में और सुधार की उम्मीद है जब बैंक अग्रणी हाउसिंग फाइनैंस कंपनी से अपना निवेश निकालेगा, जिसकी वैल्यू अभी करीब 950 करोड़ रुपये है।

एयू बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा, टेमासेक की तरफ से निवेश पूरा होना हमारे सुरक्षित खुदरा व स्थायी रूप से बढ़ रही जमा फ्रैंचाइजी, स्थिर पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, हमारे मार्जिन और बढ़त की गुंजाइश को प्रतिबिंबित करता है।

जून 2018 में सॉवरिन वेल्थ फंड ने स्मॉल फाइनैंस बैंक में 1,000 करोड़ रुपये निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। स्मॉल फाइनैंस बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 88 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 172 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 91 करोड़ रुपये रहा था। बैंक की शुद्ध ब्याज आय इस अवधि में 41 फीसदी की बढ़त के साथ 452 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 321 करोड़ रुपये रही थी।

जून 2018 में सॉवरिन वेल्थ फंड ने स्मॉल फाइनैंस बैंक में 1,000 करोड़ रु. निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी

परिसंपत्ति गुणवत्ता की बात करें तो बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां दो फीसदी पर स्थिर बनी रही, वहीं शुद्ध एनपीए 2 आधार अंक घटकर 1.1 फीसदी रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 1.3 फीसदी रही ती। इस अवधि में प्रावधान कवरेज अनुपात 44 फीसदी रहा। बैंक की उधारी 37 फीसदी बढ़कर 27,876 करोड़ रुपये रही, वहीं जमाएं 72 फीसदी बढ़कर 22,149 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। आज बीएसई में बैंक का शेयर 0.53 फीसदी टूटकर 795.10 रुपये पर बंद हुआ।

{संक्षेप में

प्रिंस पाइप्स के आईपीओ का कीमत दायरा तय

प्रिंस पाइप्स ऐंड फिटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए कीमत दायरा 177-178 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जिसके जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा, यह आईपीओ 18 को खुलेगा और 20 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी के 500 करोड़ रुपये के आईपीओ में 250 करोड़ रुपये के नए शेयर और इतना ही ओएफएस शामिल है। कंपनी ने इसका कीमत दायरा 177-178 रुपये तय किया है। जेएम फाइनैंशियल और एडलवाइस फाइनैंशियल सर्विसेज इस पेशकश की बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं और यह शेयर एनएसई व बीएसई में सूचीबद्ध होगा। देश की अग्रणी पॉलिमर पाइप्स और फिटिंग्स विनिर्माता प्रिंस पाइप्स की छह विनिर्माण इकाइयां हैं - दो दादर व नगर हवेली में है जबकि एक-एक उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में है। *एजेंसियां*

जीआईसी हाउसिंग ने जुटाए 200 करोड़ रुपये

जीआईसी हाउसिंग फाइनैंस ने शुक्रवार को कहा कि उसने आईसीआईसीआई म्युचुअल फंड से 200 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने बीएसई को बताया कि उसने 12 दिसंबर 2019 को 200 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक प्रतिभूतियां 56 दिनों के लिए आईसीआईसीआई म्युचुअल फंड को जारी किए। इन्हें 5.36 फीसदी की ब्याज दर पर आवंटित किया गया। वाणिज्यिक प्रतिभूतियां अल्पकालिक ऋण जुटाने का एक माध्यम है। इसके जरिए कंपनियां तात्कालिक जरूरतों के लिए रकम जुटाती हैं। *भाषा*

वन 97 कम्युनिकेशंस ने जुटाए 4,724 करोड़ रुपये

एजेंसियां
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने अलीबाबा की अलीपे और टी रो प्राइस प्रबंधित कोषों से 66 करोड़ डॉलर या करीब 4,724 करोड़ रुपये जुटाए हैं। नियामकीय दस्तावेजों से यह जानकारी मिली है। बिजनेस इंटेलिजेंस मंच टॉफलर के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वन97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने निवेशकों को 66 करोड़ डॉलर के शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। सॉफ्टबैंक की एसवीएफ पैंथर (केमैन) ने भी कंपनी में निवेश किया है।

दस्तावेजों में कहा गया है कि बोर्ड ने कुल 66 करोड़ 383.64 डॉलर की राशि ध्यान में रखते हुए निवेशकों को 254.58 डॉलर प्रति शेयर के बराबर सब्स्क्रिशन शेयरों के आवंटन के लिए सहमति प्रदान की है। यह प्रस्ताव 6 दिसंबर, 2019 को बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र के माध्यम से पारित किया गया है। इस संबंध में पेटीएम को भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला।

नवंबर में पेटीएम ने कहा था कि उसने अमेरिका स्थित परिसंपत्ति प्रबंधक फर्म टी रो प्राइस और मौजूदा निवेशकों - सॉफ्टबैंक तथा अलीबाबा से धन विस्तार योजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। उसने यह भी कहा था कि वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए अगले तीन वर्षों में उसकी लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।

- वन97 कम्युनिकेशंस ने अलीबाबा की अलीपे और टी रो प्राइस प्रबंधित कोषों से रकम जुटाई है
- वन97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने निवेशकों को 66 करोड़ डॉलर के शेयर जारी करने की मंजूरी दी है

भुगतान में देरी पर एक्सचेंज पहुंचे कार्वी कॉमट्रेड के क्लाइंट

कार्वी समूह की कमोडिटी ब्रोकिंग इकाई भी नकदी संकट का सामना कर रही है, हल निकालने में जुटे नियामक व एक्सचेंज

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की नाकामी का प्रसार जिंस के क्षेत्र में भी हो गया है और उसकी सहयोगी इकाई कार्वी कॉमट्रेड के क्लाइंट भुगतान से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को गिरवी शेयर के बदले उधार देने वाले बैंकों ने कार्वी कॉमट्रेड के क्लाइंटों की तरफ से की जा रही निकासी पर रोक लगा दी है, लिहाजा भुगतान में देर हो रही है।

सूत्र ने कहा, कार्वी कॉमट्रेड के जरिये सक्रियता से ट्रेड करने वाले ज्यादातर क्लाइंटों ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स), नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीएक्स) से संपर्क कर हस्तक्षेप की मांग की है।

बताया जाता है कि ये एक्सचेंज बाजार नियामक के साथ मिलकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि निवेशकों का हित सुरक्षित रहे। सूत्रों ने कहा, कार्वी समूह की कमोडिटी ब्रोकिंग इकाई भी नकदी संकट का सामना कर रही है क्योंकि एनसीडीईएक्स के साथ कुछ मसले हैं।

धोखाधड़ी के जरिये क्लाइंटों की प्रतिभूतियां गिरवी रखकर कार्वी की तरफ से उधार लिए जाने के मामले में बैंकों का साथ ब्रोकिंग फर्म का विवाद चल रहा है। कार्वी के खाते से 83,000 क्लाइंटों की गिरवी प्रतिभूतियां संबंधित क्लाइंट के खाते में हस्तांतरित करने के सेबी के कदम के बाद बैंक मुश्किल में फंस गए हैं। इन प्रतिभूतियों के बदले कर्ज देने वाले बैंकों ने इसे चुनौती दी है।

बैंकों ने हालांकि कार्वी कॉमट्रेड के खाते से निकासी पर रोक लगा दी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने ब्रोकिंग या कमोडिटी कारोबार के लिए उधार की की सुविधा अभी रोक दी है।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा, चूंकि दोनों कारोबार अलग-अलग इकाइयों के जरिए होता है लिहाजा यह कदम अतिशय है।

एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा, अगर लेनदारों की तरफ से उठाया गया कदम कार्वी कॉमट्रेड की देनदारी को लेकर है तो इसे जायज ठहराया जा सकता है। हालांकि स्टॉक ब्रोकिंग इकाई की गड़बड़ी के लिए वे कमोडिटी क्लाइंटों के पास नहीं जा सकते।

कार्वी कॉमट्रेड अक्टूबर से ही नकदी प्रवाह से जुड़े मसलों का सामना कर रही है। कमोडिटी फर्म ने इसकी वजह अरंडी वायदा बताई है, जिसने मार्जिन में डिफॉल्ट किया था और सि कारण कीमत में 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई।

हालांकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने डिफॉल्ट करने वाले कुछ सदस्यों से रकम की रिकवरी कर ली है। बताया जाता है कि फर्म अन्य क्लाइंटों से भी रकम वसूलने की प्रक्रिया में है, जो मार्क-टु-मार्केट देनदारी का भुगतान करने में नाकाम रहे थे। यह कंपनी 200-300 क्लाइंटों को सेवाएं देती है। शुरू में 30 क्लाइंट प्रभावित हुए थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ रही है। सूत्र ने कहा, बैंक हर तरह की गिरवी की समीक्षा कर रहे हैं, खास तौर से स्टॉक ब्रोकिंग इकाइयों से जुड़े गिरवी। वे स्टॉक ब्रोकर के लिए उपलब्ध बैंक गारंटी की अवधारणा पर विचार कर रहे हैं।

ब्रोकर मूल रूप से बैंक गारंटी का इस्तेमाल अपने क्लाइंटों के लिए पोजीशन लेने या अतिरिक्त निवेश पर करते हैं। उच्च उतारचढ़ाव वाले जिंस क्षेत्र में बैंक क्रेडिट के जरिए निवेश की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने बैंकों को ब्रोकरों से न्यूनतम 50 फीसदी नकद मार्जिन लेने का निर्देश दिया है और इसके बाद ही उनके बदले एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स और एनएमसीई जैसे एक्सचेंजों को गारंटी जारी करे।

विशेषज्ञों ने कहा कि लेनदारों की तरफ से कारोबारी मॉडल की समीक्षा कार्वी घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिसके बारे में बैंकों को संदेह है कि सेबी के 20 जून के परिपत्र का उल्लंघन करते हुए उनके पास क्लाइंटों की प्रतिभूतियां गिरवी रखी गई।

- एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स और आईसीएक्स पर एक साल में **6,000-8,000** क्लाइंटों के साथ सक्रिय

बढ़ रहा संकट

- कार्वी समूह की सहायक कॉर्वी कॉमट्रेड अलग इकाई के तौर पर हो रही है परिचालित
- कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के खिलाफ सेबी के **22** नवंबर के आदेश का कमोडिटी कारोबार पर कोई असर नहीं
- नियामक कार्वी समूह से जुड़े हर कारोबार पर नजर रख रहा है
- सेबी की तरफ से **83,000** क्लाइंटों के प्रतिभूतियां हस्तांतरित किए जाने के बीच लेनदारों ने कदम उठाया

सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार

एजेंसियां
मुंबई, 13 दिसंबर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 दिसंबर को समाप्त हफ्ते में 2.342 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 453.422 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। पिछले हफ्ते मुद्रा भंडार 2.484 अरब डॉलर बढ़कर 451.08 अरब डॉलर पहुंचा था। शुक्रवार को जारी आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

समीक्षाधीन हफ्ते में मुद्रा भंडार में इजाफा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी के कारण हुआ, जो कुल भंडार का अहम हिस्सा है और यह 1.891 अरब डॉलर बढ़कर 421.258 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

समीक्षाधीन हफ्ते में सोने का भंडार 43 करोड़ डॉलर बढ़कर 27.078 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आईएमएफ के साथ विशेष आहरण अधिकार 50 लाख डॉलर बढ़कर 1.441 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में देश के भंडार की स्थिति 1.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 3.644 अरब डॉलर रहा।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की जांच में नए आईपीओ फेल

रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्मों के रिटर्न पर कमजोर प्रशासन का पड़ता रहा है असर

सचिन मामबटा
मुंबई, 13 दिसंबर

हाल में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पेश करने वाली कंपनियों का गवर्नेंस के मोर्चे पर प्रदर्शन कॉरपोरेट बेंचमार्क सूचकाकों में शामिल कंपनियों के मुकाबले खराब रहा है। यह जानकारी विभिन्न कंपनियों के गवर्नेंस के मानकों की सालाना जांच से मिली।

हाल में सूचीबद्ध कंपनियों का स्कोर 54 रहा है जबकि एसऐंडपी बीएसई 100 कंपनियों व एसऐंडपी सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का स्कोर क्रमश: 58 और 61 रहा। यह जानकारी गवर्नेंस फर्म इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (आईआईएएस) की इंडियन कॉरपोरेट गवर्नेंस स्कोरकार्ड रिपोर्ट से मिली। यह ढांचा एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज बीएसई और इंटरनैशनल फाइनैंस कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इस पहल को जापान सरकार से वित्तीय सहयोग भी मिला।

इस अध्ययन में 50 कंपनियों का दोबारा मूल्यांकन किया गया, जो अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच सूचीबद्ध हुए थे।

इसमें कहा गया है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के विनियमन से बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के स्कोर में ज्यादा स्थिरता देखने को मिली है। आईपीओ कंपनियां का मामला इस लिहाज से ठीक नहीं रहा है और आईपीओ कंपनियों का औसत स्कोर पिछले साल के 55 के मुकाबले घटकर 54 रह गया है। साथ ही कंपनी का सबसे कम स्कोर 29 रहा है। अध्ययन बताता है कि बाजारों ने ज्यादा स्थिर व बेहतर प्रशासन वाली कंपनियों को पुरस्कृत किया है।

इसमें कहा गया है कि आईपीओ कंपनियों के साथ कुछ मसले बने रहे, जहां कंपनी प्रशासन के मानकों को दुरुस्त करने की जरूरत महसूस हो रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है, आईपीओ कंपनियों बात करें तो कुछ फर्मों के गंभीर मसलों की जानकारी अंकेक्षकों ने दी। इसके परिणामस्वरूप जिन कंपनियों के वित्तीय विवरण को लेकर अंकेक्षकों ने चिंता जताई उनकी संख्या साल 2018 में 24 फीसदी से बढ़कर 32 फीसदी हो गई। एसऐंडपी बीएसई 100 कंपनियों के मामले में यह संख्या हालांकि 35 फीसदी से घटकर 25 फीसदी रह गई।

ये स्कोर शेयरधारकों के साथ व्यवहार, खुलासा और पारदर्शिता समेत अन्य चीजों के आधार पर तय किए गए हैं। इसके अलावा निदेशक मंडल और शेयरधारकों की भूमिका को ध्यान में रखा गया है। दिलचस्प रूप से एसऐंडपी बीएसई 100 में शामिल अलग-अलग प्रवर्तक समूह की कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का स्कोर सबसे कम रहा। ऐसी कंपनियों का स्कोर 52 रहा जबकि निजी प्रवर्तक वाली कंपनियों का स्कोर 60 रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्कोर सबसे ज्यादा 63 रहा। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या और संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन समेत अन्य मसलों पर पारदर्शिता के अभाव भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रशासन के स्कोर पर असर डाल रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस वाली फर्मों का रिटर्न वास्तविक रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि 60 या इससे ज्यादा गवर्नेंस स्कोर वाली कंपनियां (जो अच्छे प्रशासन वाली श्रेणी में मानी जाती है) ने दो से तीन वर्ष की अवधि में बाकी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया।

स्रोत : इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया (आईआईएएस)

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक का शेयर टूटा

एजेंसियां
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता के दौरान गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करने वाले उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक का शेयर एक दिन बाद यानी शुक्रवार को मुनाफावसूली के चलते करीब 7 फीसदी टूट गया। बीएसई पर यह शेयर 6.89 फीसदी टूटकर 52.05 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 8.49 फीसदी तक टूट गया था। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह शेयर 6 फीसदी टूटकर 52.55 रुपये पर बंद हुआ। कारोबारी वॉल्यूम के लिहाज से बीएसई पर 27.97 लाख शेयरों का लेनदेन हुआ जबकि एनएसई पर 4 करोड़ शेयरों का लेनदेन हुआ। गुरुवार को उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक का शेयर 57 फीसदी की बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ था जबकि इसकी आईपीओ कीमत 37 रुपये थी, लेकिन अंत में 51 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ था।

कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 2 से 4 दिसंबर तक खुला था और 36-37 रुपये के कीमत दायरे पर उसे 165 गुने से ज्यादा की बोली मिली थी।

संक्षेप में

मार्च 2020 तक आ सकती है आर्थिक गणना

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया सातवीं आर्थिक गणना रिपोर्ट मार्च 2020 तक दे सकती है। एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. विशेष उद्देश्य कंपनी है जिसका गठन कंपनी कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। इसका मकसद साझा सेवा केंद्र योजना (सीएससीएस) के क्रियान्वयन पर नजर रखना है। *भाषा*

स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए मांगी गई बोलियां

दूरसंचार विभाग ने 4.98 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 8,526 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी करवाने के लिए एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित की हैं। इनमें से कुछ स्पेक्ट्रम 5जी सेवाओं के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। दूरसंचार विभाग के आग्रह प्रस्ताव (आरएफपी) के अनुसार इच्छुक कंपनियां अपनी बोलियां 13 जनवरी तक दे सकती हैं। इसके लिए वित्तीय बोलियां 24 जनवरी को खोली जाएंगी। *भाषा*

बैंकों के फंसे ऋण बढ़ेंगे: मूडीज

संकटग्रस्त रियल एस्टेट और एनबीएफसी क्षेत्र को बैंकों ने दिए हुए हैं बड़ी मात्रा में ऋण

अभिजित लेले
मुंबई, 13 दिसंबर

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज कहा कि भारतीय बैंकों को ऋणग्रस्त वित्त कंपनियां और झटके दे सकती हैं। मुश्किल दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को दिए हुए ऋणों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की खुदरा एवं एसएमई कर्जदारों को ऋण देने की क्षमता कमजोर होने से बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव बढ़ेगा।

मूडीज ने कहा कि बैंकों ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी मात्रा में कर्ज दिया हुआ है, इसलिए उन पर जोखिम है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बैंक क्षेत्र के अहम मानकों में सुधार का रुझान पलटने या धीमा पड़ने के प्रबल आसार हैं क्योंकि एनबीएफसी क्षेत्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है।

बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर असर

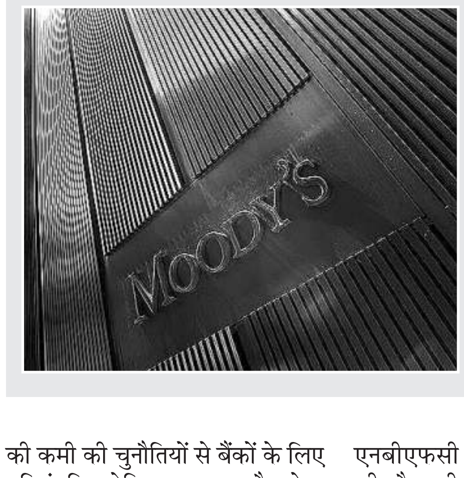

- एनबीएफसी और रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी मात्रा में कर्ज दिया होने से बैंकों पर जोखिम
- बैंक क्षेत्र के अहम मानकों में सुधार का रुझान पलटने या धीमा पड़ने की प्रबल संभावना

भारत की एनबीएफसी के पास धन की कमी की चुनौतियों से बैंकों के लिए परिसंपत्ति जोखिम बढ़ रहा है। ऐसा उस अर्थव्यवस्था में हो रहा है, जिसकी बीते वर्षों में गैर-बैंक ऋणदाताओं पर निर्भरता लगातार बढ़ी है। यह बैंकों के कर्ज के लिए नकारात्मक है। भारत की एनबीएफसी और बैंक नकारात्मक फीडबैक की सुरंग में फंस गए है। उन्हें ऋण घटाने, और कर्जदारों पर ऋण लौटाने का दबाव बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसके नतीजतन ऋण डिफॉल्ट हो रहे हैं और एनबीएफसी का संकट और गहरा रहा है। मूडीज के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ ऋण अधिकारी श्रीकांत वादलामणि ने कहा, 'एनबीएफसी में पैदा होते दबाव का मतलब है कि उन्हें ऋण देने वाले भारतीय बैंकों के फंसे कर्जों में बढ़ोतरी होने के बहुत अधिक आसार हैं।'

रियल एस्टेट क्षेत्र में संकट साफ नजर आ रहा है, जिसमें आम तौर पर डेवलपरों के पास अपने कर्ज चुकाने के लिए नकदी की कमी हो जाती है और वे अपनी कर्ज देनदारी पूरी करने के लिए एनबीएफसी से मिलने वाले कर्ज पर निर्भर हैं। रियल एस्टेट कंपनियां पहले ही दबाव झेल रही हैं। ऐसे में अगर उन्हें फंड मिलने में दिक्कत आती है तो उन पर दबाव और बढ़ेगा और उनका ऋण देने के मामले में प्रदर्शन और कमजोर पड़ेगा। खुदरा और लघु एवं मझोले उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी संकट है। ये दोनों क्षेत्र हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े हैं और एनबीएफसी से मिलने वाले धन पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

'वादे के मुताबिक हो रहा पूंजीगत व्यय'

इंदिवल धस्माना
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 32 महारत्न और नवरत्न कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक 98,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है। ये कंपनियां चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में 60,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च और करेंगी।

इन पीएसयू के कुल पूंजीगत व्यय 1.58 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा उस आंकड़े से 3,000 करोड़ रुपये अधिक है, जिसका वित्त मंत्रालय ने सितंबर में वादा किया था। यह आंकड़ा मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में पेश किया। सुब्रमण्यन ने कहा कि इसके अलावा रेलवे और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के इस महीने के अंत तक 2.46 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर घटकर छह साल के निचले स्तर 4.5 फीसदी पर आ गई। ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था अभी संकट से बाहर नहीं निकली है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) अक्टूबर में 3.8 फीसदी गिरा है, जिसमें लगातार तीसरे महीने गिरावट रही है। वहीं खुदरा महंगाई की दर नवंबर में 40 महीनों के सर्वोच्च स्तर 5.54 फीसदी पर पहुंच गई।

इस संवाददाता सम्मेलन से इतर सुब्रमण्यन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अवस्फीति नहीं है। अवस्फीति में एक ही समय मंदी और महंगाई होती है। उन्होंने कहा कि महंगाई में बढ़ोतरी कुछ समय ही रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आवास, निर्यात, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाहन जैसे क्षेत्रों के लिए पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी के उपाय किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि अन्य कोई क्षेत्र सरकार के पास मदद के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सरकार सोमवार से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा शुरू करेगी।

सुब्रमण्यन ने अपनी प्रस्तुति में यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कंपनियों को 2.2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए हैं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को 72,985 करोड़ रुपये और खुदरा कर्जदारों को 39,453 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों के दौरान 32 पीएसयू के 62 फीसदी बकाये चुका दिए गए हैं। अब केवल 4,877 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी है। सुब्रमण्यन ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 15 नवंबर तक उनके 12,698 करोड रुपये के बिल डिस्काउंट किए गए हैं।

वादे पर काम

- 32 पीएसयू ने नवंबर तक 98,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय किया
- वित्त वर्ष की शेष अवधि में करेंगे 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्ति व्यय
- वित्त मंत्रालय ने सितंबर में करीब 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का किया था वादा
- सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है मकसद

अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने पर मोदी सरकार का ध्यान

पृष्ठ 1 का शेष

इनमें कई प्रस्तुतियां अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी जानी थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण इन्हें तब टाल दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तुतियों के आलवा पीएमओ ने बजट पर विभिन्न मंत्रालयायें और सचिवों से उनके सुझाव भी मांगे हैं।

बजट से पहले इनके साथ विभिन्न खंडों को लेकर बैठकें आयोजित होंगी। जैसा कि पहले खबरें आई थीं, 2019-20 के बजट के कुछ प्रस्ताव वापस लिए जाने के बाद सरकार में राजनीतिक नेतृत्व ने 2020-21 के लिए बजट निर्माण प्रक्रिया का नियंत्रण मोटे तौर पर अपने हाथों में ले लिया है। आगामी बजट में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरमार में उच्च स्तर पर इस दिशा में पहल हुई है। वित्तीय प्रणाली में अधिक नकदी सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए आगामी बजट में दीर्घ अवधि का पूंजी लाभ समाप्त किया जा सकता है और लाभांश वितरण कर का बोझ कंपनियों के बजाय शेयरधारकों पर डाला जा सकता है। इसके साथ ही बजट में वेतनभोगी वर्ग को आयकर से थोड़ी और राहत और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए कर रियायत की घोषणाएं की जा सकती हैं।

आम तौर पर प्रधानमंत्री बजट से पहले अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों से बैठक करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत के मद्देनजर यह कार्यक्रम अधिक महत्त्पूर्ण हो जाता है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर महज 4.5 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसके बाद अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर चिंताए बढ़ गई हैं।

हृदय और मधुमेह के मरीजों को राहत

इस साल तीन अहम दवाओं का पेटेंट खत्म, जिनकी कीमतों में आई 80 फीसदी कमी

सोहिनी दास
मुंबई, 13 दिसंबर

देश में हृदय और मधुमेह के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इस साल मधुमेह और हृदय से संबंधित तीन प्रमुख बीमारियों की दवाओं का पेटेंट खत्म हो गया है और घरेलू कंपनियों ने बाजार में मूल दवाओं के सस्ते जेनेरिक संस्करण उतारे हैं। इन दवाओं की कीमतें पहले ही करीब 80 फीसदी घट चुकी हैं। अच्छी खबर यह है कि मधुमेह की कुछ और दवाओं का पेटेंट अगले दो-चार साल में खत्म होने जा रहा है। इससे भारत के 7.3 करोड़ मधुमेह के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

स्विटजरलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी नोवार्तिस की गैल्वस (विल्डाग्लिपटिन) का पेटेंट दिसंबर में खत्म हो गया है। पहले मधुमेह के मरीजों का प्रति खुराक (मरीज को रोजाना दो खुराक की जरूरत होती है) का खर्च 20 से 25 रुपये आता था, जो अब घटकर 5 से 6 रुपये प्रति खुराक या रोजाना करीब 10 रुपये रह गया है।

इस महीने की शुरुआत में अहमदाबाद की एरिस लाइफसाइंसेज ने विल्डाग्लिपटन आधारित फॉर्मूलेशन के लिए 93 करोड़ रुपये में नोवार्तिस से जोमेलिस खरीदी है। इस बाजार में तेजी से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस बाजार में पहले ही 30 नए ब्रांड उतर चुके हैं। इसमें देश की हर प्रमुख दवा कंपनी आ गई है। इन कंपनियों में टोरेंट, जाइडस, इन्टास, ल्यूपिन, पैनेसिया, सिप्ला, जूवेंट्स, एमक्योर आदि शामिल हैं। इस बाजार का आकार करीब 900 करोड़ रुपये है।

हृदय से संबंधित बीमारी की दवा टीकाग्रेलोर (एस्ट्राजेनेका ब्रिलिंटा के नाम से बेचती है) का पेटेंट इस साल खत्म हो गया है। ब्रिस्टोल-मायर्स सिक्वब की खून को पतला करने वाली दवा इलिक्विस पर पेटेंट की अवधि खत्म होने को लेकर मुकदमा चल रहा है। एक पेटेंट इस महीने खत्म हो रहा है, जबकि इसे इजाद करने वाली कंपनी का दावा है कि एक अन्य पेटेंट इसे सितंबर 2022 तक सुरक्षित करता है।

हैदराबाद की नैटको फार्मा पहले ही खून को पतला करने वाली जेनेरिक दवा (नाम एपिगाट) शुरू करने की कोशिश कर चुकी है और यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। यह उत्पाद शुरू कर रही मुंबई की एक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'घरेलू कंपनियां खून को पतला करने वाली दवा के जेनेरिक संस्करण शुरू करने के लिए तैयार हैं। ज्यादातर कंपनियां इसे शुरू करने के लिए नैटको का रास्ता ही अपनाएंगी।'

टीकाग्रेलोर उन मरीजों को खाने की सलाह दी जाती है, जिन्हें हृदय से संबंधित बीमारी रही है ताकि दिल के दौरे के आसार कम किए जा सकें। यह दवा रक्त के थक्कों को भी कम करती है। टीकाग्रेलोर की कीमत करीब 55 रुपये प्रति खुराक है। लेकिन अब कीमत 12 रुपये तक आ गई है। इस दवा की औसत कीमत 20 रुपये प्रति खुराक है।

मीठी गोली...

- मधुमेह की दवा विल्डाग्लिपटिन और हृदय से संबंधी बीमारी की दवा टीकाग्रेलोर का पेटेंट खत्म
- ब्रिस्टोल-मायर्स सिक्वब की खून को पतला करने वाली दवा इलिक्विस का पेटेंट जल्द खत्म होने की संभावना

आईआईटी में बढ़ीं नौकरियां

विनय उमरजी और एजेंसियां
अहमदाबाद, 13 दिसंबर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के पुराने संस्थानों के प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आईआईटी हैदराबाद में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अंतिम प्लेसमेंट प्रक्रिया के पहले चरण में अंतरराष्ट्रीय नौकरी प्रस्तावों में 72 प्रतिशत का उछाल आया है। दूसरी ओर, आईआईटी खड़गपुर के एक अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट प्रक्रिया के पहले चरण में 1,310 छात्रों को नौकरी प्रस्ताव मिले हैं।

आईआईटी हैदराबाद में प्लेसमेंट प्रक्रिया के फैकल्टी इंचार्ज प्रदीप येमुल्ला ने बताया कि संस्थान के छात्रों को अभी तक अमेरिका, जापान, ताइवान की 18 कंपनियों से कुल 38 नौकरी प्रस्ताव मिले हैं जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 22 थी। प्लेसमेंट प्रक्रिया के पहले चरण की समाप्ति पर आईआईटी हैदराबाद में कुल 96 कंपनियों ने 271 छात्रों को नौकरियां दी हैं जिसमें 37 प्री-प्लेसमेंट नौकरी प्रस्ताव भी शामिल हैं। संस्थान में कुल 483 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण कराया था।

स्कूलों में उद्यमिता के गुर सिखाएंगी महिला उद्यमी

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब महिला उद्यमी छात्रों को उद्यमिता के गुर सिखाएंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार की एक अहम महिला उद्यमी संगठन से समझौता करने की भी योजना है ताकि छात्रों को शुरू से ही उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन (एफएलओ) की महिला उद्यमियों से कहा कि सरकार चाहती है कि बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के समय से ही कारोबारी मानसिकता वाले बनें। इसलिए दिल्ली सरकार ने इस वर्ष से सरकारी स्कू लों में उद्यमिता पाठ्यक्रम शुरू किया है और छात्रों को कारोबारी आइडिया के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। केजरीवाल ने कहा, 'हम चाहते हैं कि महिला उद्यमी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उद्यमिता पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे इन छात्रों को उद्यमिता के गुर सिखाएं। महिला उद्यमी उनको बताए कि कारोबार कैसे खड़ा किया जा सकता है और अपने कारोबारी अनुभव भी उनके साथ साझा करें।' केजरीवाल ने एफएलओ के सामने सरकारी स्कूलों में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमिता पढ़ाने के लिए सरकार के साथ समझौता करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर एफएलओ की अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार ने कहा कि हमें सरकार का यह प्रस्ताव स्वीकार है और जल्द ही यह समझौता कर महिला उद्यमी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों को उद्यमिता के गुर सिखाएंगी।

केजरीवाल ने महिला उद्यमियों से अपील की कि वे पंजाब और हरियाणा में पराली से सीएनजी और कोयला बनाने के लिए संयंत्र स्थापित करें। केजरीवाल ने महिला उद्यमियों से कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिलाओं को भरपूर मौका देगी और दिल्ली में उनको आने वाली दिक्कतों को भी दूर करेगी। सरकार दिल्ली के कार्यबल में महिलाओं की महज 11 फीसदी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहती है। इसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से भी मदद मिलेगी।

बीएस बातचीत

सीएसबी बैंक के बदलाव से सहमत निवेशक

पहले कैथलिक सीरियन बैंक के रूप में पहचान रखने वाला सीएसबी बैंक अपने 100वें साल में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुआ और इसके 410 करोड़ रुपये के आईपीओ को 86.89 गुना अभिदान मिला। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी **सीवीआर राजेंद्रन** की करीब 22 महीने पहले फेयरफैक्स को 1,200 करोड़ रुपये सीएसबी में निवेश करने के लिए राजी करने में अहम भूमिका रही है। उन्होंने इन मुद्दों पर **टी ई नरसिम्हन** से बातचीत की कि किस चीज से निवेशक सहमत हुए, एनबीएफसी के खिलाफ बैंक खुद को कैसे पेश करना चाहता है और उसकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। बातचीत के अंश :

ऐसे कौनसे कारक हैं, जिन्होंने निवेशकों को लुभाया है और सीएसबी के आईपीओ को शानदार सफलता दिलाई है?
निवेशक हमारे रूपांतरण की कहानी और नए निजी क्षेत्र के मॉडल की तरफ यात्रा से सहमत हैं। यह कार्य प्रगति पर है, लेकिन वे उसी कार्य से खुश हैं, जो हमने अब तक किया है। वे बिना पूंजी के पिछले तीन साल के दौरान स्वर्ण ऋण और अग्रिमों में वृद्धि से भी प्रभावित हैं। बैंक ने अपने अग्रिम पोर्टफोलियो बढ़ाया है, लेकिन हमने जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में कमी की है और पोर्टफोलियो बढ़ाया है। निवेशकों ने कंपोजिशन में इस बदलाव को पसंद किया है। सीएसबी का नेटवर्क और छोटी जमा का आधार अन्य कारक हैं। इसके अलावा बैंक का एनपीए उद्योग के स्तर से कम है। हमने खुद को बड़े बैंक नहीं बल्कि एनबीएफसी के प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया है, जिससे निवेशक खुश हैं।

इस समय आपके सामने क्या चुनौतियां हैं?
बाजार में खुद को साबित करने के लिए कारोबार को बढ़ाना। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम एनपीए और पीसीआर को मौजूदा स्तरों पर बनाए रखने और आने वाले समय में सुधार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी से यह चुनौती बन सकता है। हमें आय ती तुलना में लागत के अनुपात को घटाने की अफनी क्षमता साबित करने की जरूरत है। यह 103 से घटकर 71 पर आ गया है। निवेशक चाहते हैं कि हम इसे घटाकर 50 से नीचे लाएं।

आपने कारोबार को बढ़ाने की क्या योजनाएं बनाई हैं?
हर 1,700 करोड़ रुपये की वृद्धि- 1,000 करोड़ रुपये की जमाओं और 700 करोड़ रुपये के अग्रिमों से हम करीब 30 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित कर सकते हैं। सीएसबी को फेयरफैक्स से करीब 1,208 करोड़ रुपये की पूंजी मिली है। इसके अलावा निर्गम से करीब 25 करोड़ रुपये मिले हैं। हम इस पूंजी और 33 फीसदी स्वर्ण ऋण और शेष जोखिम भारत परिसंपत्तियों के मिश्रण की मदद से अतिरिक्त पूंजी की जरूरत के बिना बैलेंस शीट को दोगुना कर सकते हैं।

आपका लक्ष्य क्या है?
मूल रूप से हमने 25 फीसदी से कम वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया था। हम 100वें साल में हैं, इसलिए हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम 100वें वर्ष में और अधिक वृद्धि दर्ज कर सकते हैं ताकि दुनिया को बढ़ने की हमारी क्षमता दिखाई जा सके।

पिछले साल सीएसबी को नुकसान हुआ था...
हमें 98 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान और समय-पूर्व सेवानिवृत्ति जैसे कर्मचारी प्रावधानों के कारण 100 करोड़ रुपये का एकबारगी नुकसान हुआ था। हमने इस साल की पहली छमाही में 44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। हमारा परिचालन लाभ करीब 104 करोड़ रुपये था।

आप सीएसबी को कैसे स्थापित करना चाहते हैं?
जहां तक ऋण देने का सवाल है, नई पीढ़ी का कोई भी बैंक एनबीएफसी क्षेत्र में ज्यादा काम करेगा। सूक्ष्म वित्त, एमएसएमई, दोपहिया, पुराने ट्रक जैसे क्षेत्रों में प्रतिफल अधिक है।

बीएस सूडोकू 3612

	7		3					8
				8				7
	5	6			9			
	9			3				2
		7	4	2	6	8		
1				7			6	
			8			5	2	
7				6				
2					4		7	

परिणाम संख्या 3611

2	7	4	9	8	5	6	1	3
8	5	3	2	6	1	4	9	7
9	6	1	3	4	7	5	8	2
1	3	2	8	7	4	9	5	6
6	8	9	1	5	3	7	2	4
7	4	5	6	9	2	8	3	1
5	2	6	7	3	8	1	4	9
3	9	8	4	1	6	2	7	5
4	1	7	5	2	9	3	6	8

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2080/2090, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1580/1660,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1445, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1528, फ्लैक 1458, डीएमओ 1040, टरपीन लैस बोल्ड 1552

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1060/1200, खुरपा 1000/1080,चाकू 1050/1230, रसकट 850/880, शक्कर 1180/1200, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3325, सिहोरा 3165, बुंदकी 3190, बुढ़ाना 3270,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/1000, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4350, खल: सरसों 2200/2300, बिनौला 2400/2500, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2140/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3780/3800, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4600/4625,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3825, जौ 2060/2070,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 7200/7300, बाजरा (गुजरात) 1900/1910, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4100/4200, काबली चना 4700/5900, मूंग 6000/6200,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2000, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्यूअस 1250,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9500/10500, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3970/4000, हरियाणा 3960/3980, राजस्थान 3880/3970, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2190/2200,

फाजिल्का
गेहूं 2130/2140, सरसों 4325/4350 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000,कपास देशी 4850/4950, कपास नरमा (क्विं.) 5100/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2100/2120, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2300/2310, बिहार 2365/2370, दाल उड़द छिलका 8800/10700, चना देशी 4950/5025, दाल चना 5075/5275, काबली चना 4800/5700, राजमां चित्रा पुणे 6700/8000, चीन 7000/7600,

करनाल
गेहूं दड़ा 2130/2140, बासमती चावल 6400/6500, धान 1121 नं. 2800/2850, पूसा 1509 धान 2500/2575, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5150/5200, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3750/3800, सरसों 4150/4200, गेहूं 2140/2150, नरमा कपास 5050/5150

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4200/4250, खल बिनौला मोटी 2300/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 8850/9000, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1800/1850 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 256

अलग-अलग रुख

अर्थव्यवस्था को लेकर अलग-अलग रुख अपनाया जा रहा है और सत्ताधारी दल की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि उनकी अनदेखी करनी संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आरंभ से ही यह स्पष्ट रहा है कि सरकार के लिए राजनीति अर्थव्यवस्था से ऊपर है। ऐसा 2014 में मोदी के लंबे चौड़े भाषण के बावजूद था। आज यह कहीं अधिक स्पष्ट है: अर्थव्यवस्था की महत्ता आज राजनीतिक संबद्धता के बुनियादी नियमों से भी कमतर रह गई है जहां संघ परिवार के लंबे समय से चले आ रहे नारों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप दलील दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी जनादेश हासिल किया है। जब इंदिरा गांधी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थीं। तब जनादेश और बड़ा था। इसके चलते ही उन्होंने वाम रुझान वाली आर्थिक नीति अपनाते हुए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण किया, प्रतिबंधात्मक श्रम कानून बनाए और तथा ऐसे ही अन्य कानून पारित किए। उन्होंने भू-कानूनों को भी कड़ा किया। अर्थव्यवस्था आज तक राजनीति को दी गई उस वरीयता की कीमत चुका रही है। क्या इतिहास अपने आपको दोहराएगा?

बड़े बदलाव टुकड़ों में नहीं आते हैं और फिलहाल काफी कुछ छिटपुट तरीके से हो रहा है। यह सब उस नई बहस का हिस्सा हो सकता है जिसमें राष्ट्रीय नागरिक पंजी द्वारा संभावित अशांति भी शामिल है। भाजपा चाहे जितनी दबदबे वाली पार्टी बन गई हो, घरेलू राजनीतिक हालात दर्शाते हैं कि केंद्र और राज्य के स्तर पर तस्वीर एकदम विरोधाभासी है। भाजपा के लिए चुनौतियां लगातार बरकरार हैं। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ हिंदी प्रदेश में जीत सुनिश्चित करने के उसके प्रयास ने उसे तमाम तरह की अल्पसंख्यक आबादी के सामने ला खड़ा किया है। इसके परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पूर्वोत्तर में इनर लाइन जैसी परिवर्ती व्यवस्था अब स्थायी स्वरूप ले रही है और इसका विस्तार हो रहा है। इससे देश नये तरीके से बंट रहा है। असम में नये सिरे से समस्या शुरू हो गई है जबकि कश्मीर में आम जनता लगातार पांचवें महीने तमाम प्रतिबंधों से गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक देशों ने जिन वजहों से अधिनायकवादी चीन पर भारत को तवज्जो दी थी और उसके साथ आपसी रिश्ते कायम किए उन पर भी अब सवालिया निशान लग गए हैं। अमेरिका और यूरोप में आलोचना की जा रही है जो आगे और बढ़ेगी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में प्रतिक्रिया नजर भी आने लगी है। कमजोर भारतीय अर्थव्यवस्था के चलते चीन से मिल रही चुनौती का सामना करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उसने भारत की तरह अपनी गति नहीं खोई है। दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के नाते भारत आकर्षक बाजार बना रहेगा लेकिन उसने जो गति खो दी उसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर आएगा। आर्थिक कूटनीति के मामले में हालात उलट गए हैं जिससे हम अप्रभावित नहीं रह सकते। सन 2020 में अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक सुधार की अपेक्षा की जा सकती है लेकिन तत्काल पहले जैसी तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने की राह में बड़ी बाधाएं हैं। वित्तीय क्षेत्र की दिक्कतें कायम हैं और छोटे और मझोले उपक्रम संघर्षरत हैं। कृषि के मोर्चे पर दिक्कत है और निर्यातक मुद्रा नीति के कारण परेशानी में हैं। वृहद आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो राजकोषीय स्थिति बुरी है क्योंकि केंद्र अपने बिल तक चुकाने की स्थिति में नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कुछ बुनियादी समस्या हैं जो कर के मोर्चे पर भी दिक्कतदेह बनी हुई हैं। चुनाव पूर्व कर दरों में कमी ने हालात और खराब किए। मौद्रिक नीति की अपनी सीमाएं हैं और बहुत अधिक गुंजाइश नजर नहीं आ रही। जीएसटी राजस्व में कमी के कारण सरकार की निजी बेहतरी की प्रतिबद्धताएं अब मुश्किल में हैं। इनमें चुनाव पूर्व किसानों को धन राशि देने का वादा भी शामिल है। इन वादों पर अमल अपने साथ राजकोषीय फिसलन लाएगा और इसके लिए ऋण लेना पड़ सकता है जो जीडीपी के अनुपात में सरकारी कर्ज में इजाफा करेगा। परिवहन के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश से भी अपेक्षित प्रतिफल नहीं मिला जबकि बिजली क्षेत्र में अव्यवहार्यता बरकरार है।

भाजपा की राजनीतिक दबदबे और संबद्धता के नियमों का पुनर्लेखन बताता है कि उसकी प्राथमिकताएं कितनी गलत हैं। ऐसे में शायद वापसी मुश्किल हो जाए। अनुमान यह है कि अगले आम चुनाव से पहले आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी लेकिन अगर मौजूदा दिशा नहीं बदली गई तो ऐसे अनुमान गलत साबित होंगे। सरकार को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

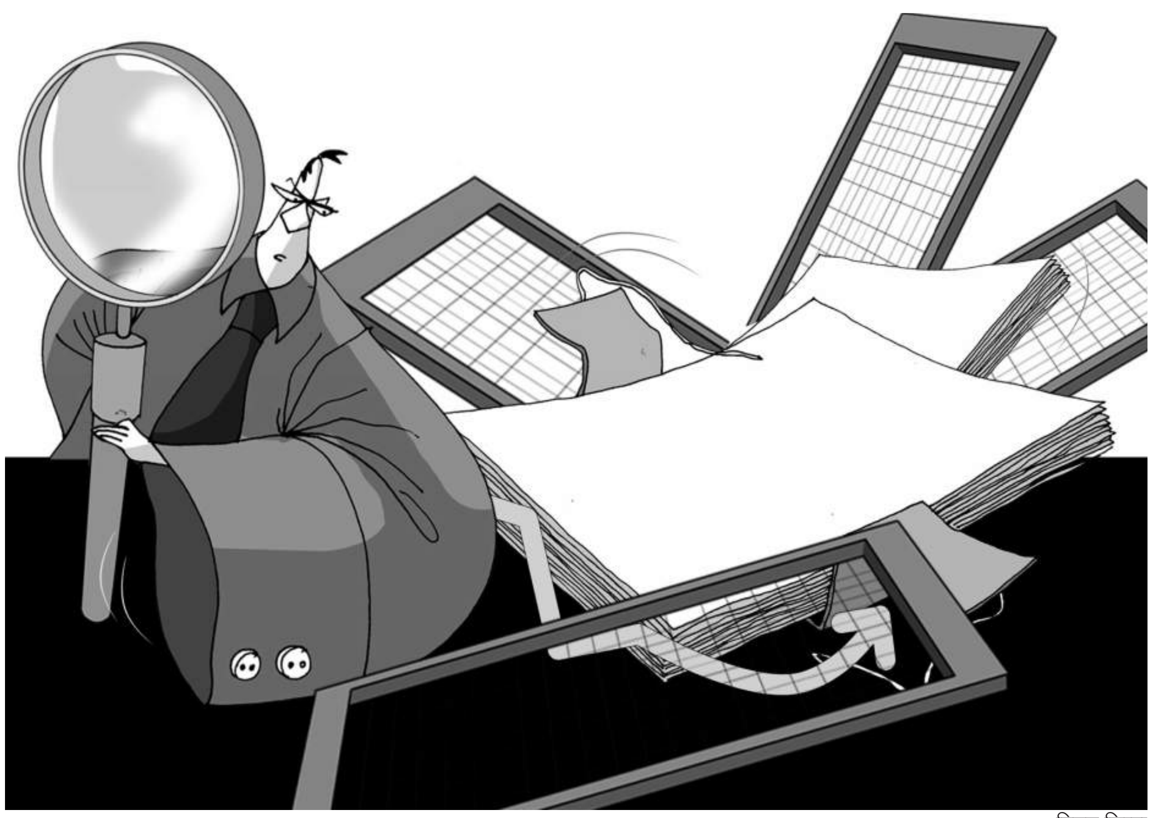

विनय सिन्हा

एक सांख्यिकीय संस्थान का दम तोड़ रहा वजूद

हालिया विवादों में उलझे एनएसएसओ को बदलते वक्त के हिसाब से अपना कामकाज दुरुस्त करने की जरूरत है। इसका विश्लेषण कर रहे हैं **सुनील के सिन्हा**

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर तैयार रिपोर्ट जारी न होने से उठे विवाद और राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) की घरेलू उपभोग पर तैयार रिपोर्ट लीक होने से संबंधित विवादों से भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। ऐसे वक्त में यह बेहद जरूरी है कि एनएसएसओ के कामकाज पर एक नजर डाली जाए।

भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली का विकास हमारी बेहद विशाल एवं विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के बारे में विभिन्न मसलों से संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए किया गया था। इस प्रणाली की प्रभावी उपलब्धियों के बावजूद आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ती रही हैं। आंकड़ों का संग्रह, सारिणीकरण और उनकी व्याख्या की समस्याएं दूर करने के लिए 1961 में भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) का गठन किया गया। फिर रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं के मुताबिक 12 जुलाई, 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग वजूद में आया।

एनएसएसओ को अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से संबंधित घरेलू एवं उद्यम जगत से जुड़े व्यापक सर्वेक्षण करने का जिम्मा दिया गया।

सरकार ने दिवंगत प्रोफेसर पी सी महालनोबिस की सलाह पर एनएसएसओ का गठन 1950 में किया था। महालनोबिस उस समय नेहरू मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार थे। राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय के कुल जोड़ की गणना के लिए उपलब्ध सांख्यिकी आंकड़ों में बड़ी खामियां पाई थीं। इन कमियों को दूर करना ही एनएसएसओ का मुख्य मकसद था। अप्रैल 1961 में सांख्यिकी विभाग का गठन किया गया और एनएसएसओ इसका अंग बना दिया गया। अक्टूबर 1999 में एनएसएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक संबद्ध कार्यालय बन गया।

एनएसएसओ ने अपने सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत अक्टूबर 1950 से मार्च 1951 के दौरान ग्रामीण इलाकों में विभिन्न मुद्दों के बारे में पड़ताल से की थी। दसवें दौर का सर्वेक्षण होने तक एनएसएसओ पूरी तरह व्यवस्थित हो चुका था। संसद में 1959 में अधिनियम पारित होने के बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) को भी वैधानिक दर्जा मिल गया। इसकी आम स्वीकृति इससे पता चलती है कि सरकारी संगठन एवं स्वायत्त संस्थान जरूरी आंकड़े जुटाने के लिए एनएसएस की सर्वे पद्धति में रुचि दिखाते थे।

सांख्यिकी मंत्रालय के एक प्रशासकीय आदेश के मुताबिक मई 2019 में एनएसएसओ को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के साथ मिलाकर नया संगठन एनएसओ बना दिया गया। हालांकि एनएसएसओ के चार प्रकोष्ठ यथावत बने रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि एनएसएसओ को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पेश करने को लेकर पहले जो थोड़ी-बहुत स्वायत्तता हासिल थी, अब वह क्षीण हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब भी कार्य-समूह एवं तकनीकी समितियां और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदा भूमिका विशुद्ध रूप से तकनीकी ही हैं। एनएसएसओ की कुछ हालिया रिपोर्ट जारी होने के पहले मीडिया में लीक होने के बाद कई तरह के आरोप लगाए गए थे।

अगले साल एनएसएसओ 70 साल पुराना संगठन हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली का एक शुभचिंतक होने और खुद इस व्यवस्था का 37 वर्षों तक हिस्सा रहने वाले शख्स के नाते मैं आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कुछ सुझाव रख रहा हूं:

- सत्ता पर काबिज सरकार को आंकड़ा संग्रह का काम प्राथमिकता में रखना चाहिए और संक्षिप्त अवधि की अनुबंधित नियुक्तियों से परहेज करना चाहिए। आंकड़े जुटाने के काम में लगे नियमित कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि किए जाने से रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे। अधिक स्वायत्तता के लिए एनएसएसओ को सांख्यिकीय आयोग के मातहत रखा जाना चाहिए। इसके अलावा सांख्यिकीय आयोग को कानूनी रूप से अधिक सशक्त भी बनाया जाना चाहिए।
- आंकड़े जुटाने के काम में लगे कर्मचारियों को मौजूदा समय की अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा का अंग होना चाहिए।
- अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा का नाम बदलकर सहयोगी सांख्यिकीय सेवा कर दिया जाना चाहिए। इसमें डेटा संग्राहकों को भी जगह दी जानी चाहिए।
- डेटा संग्राहकों की संख्या एनएसएसओ द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के नमूना आकार के आधार पर तय की जा सकती है। उन्हें उन राज्यों में तैनात करना चाहिए जहां के वे निवासी हों और वहां की स्थानीय भाषा से भी परिचित हों।
- एनएसएसओ दरों, अनुपात एवं प्रतिशत के संदर्भ में पैमानों का आकलन करता रहा है लिहाजा एनएसएस के हालिया सर्वेक्षणों का मौजूदा नमूना आकार बुनियादी मानकों के बारे में विश्वसनीय अनुमान देने के लिए पर्याप्त है।
- एनएसएसओ को अब पैनल नमूना दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जैसा कि भारत के महापंजीयक (आरजीआई) में नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के लिए किया जा रहा है। नमूना डिजाइन में इस तरह का बदलाव लाने के लिए कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी गौर करने की जरूरत पड़ सकती है।
- एनएसओ के सर्वे डिजाइन एवं शोध प्रभाग (एसडीआरडी) के लिए अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अभी तक वे बुनियादी तौर पर सर्वे सूची के डिजाइन, सारिणीकरण योजना, क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने, प्रशिक्षण और संग्रहीत आंकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने में ही लगे हुए हैं। उन्हें यूनिट स्तरीय डेटा पर आधारित अधिक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए।
- एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन प्रभाग को अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण एवं औचक निगरानी के अलावा पर्यवेक्षकों की यात्रा डायरी के विश्लेषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

(लेखक एनएसएसओ के पूर्व महानिदेशक एवं सीईओ हैं)

येदियुरप्पा और उनके पुत्र की मेहनत से कर्नाटक में जीत

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

आलोचना करने वाले फिलहाल खामोश हैं। चुनौती देने वालों ने भी अपनी तलवारें कम से कम अभी तो अपनी म्यान में रख ली हैं। बीएस येदियुरप्पा ने अपने मित्रों और खासतौर पर अपने परिवार की बदौलत ऐसी वापसी की है जो खुद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर कई के लिए ईर्ष्या की वजह बन गई होगी। ऐसे लोगों में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। फडणवीस महाराष्ट्र में मिली हार से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यह देखना चुभा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सांसदों से येदियुरप्पा का खड़े होकर स्वागत करने को कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक उपचुनाव में जीत के बाद राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरह स्थिर हो गई है।

यह सच है कि येदियुरप्पा ने उपचुनाव जीतने में अपनी सारी ताकत झोंक दी। भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में 224 में से 105 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 78 और जनता दल सेक्युलर को 37 सीटें मिली थीं। येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का प्रयास किया लेकिन वह नाकाम रहे और आखिरकार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और भाजपा को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। परंतु येदियुरप्पा के लिए यह व्यक्तिगत झटका था। जब उन्हें 2016 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्हें काफी गुटबाजी संभालनी पड़ी। कुरुबा (गड़रिया) समुदाय के के एस ईश्वरप्पा ने अपनी जाति के लोगों को एकजुट किया और लिंगायत (येदियुरप्पा) और वोक्कालिंगा (एचडी देवेगौड़ा) दोनों समुदायों से मुकाबला किया जा सके। वोक्कालिंगा सदानंद गौड़ा और लिंगायत जगदीश शेट्टार को कई शिकायतें थीं। उन्हें बीएल संतोष के रूप में एक सुनने वाला मिला जो आरएसएस और भाजपा के बीच समन्वयक थे। इन बातों से निजात पाना आसान नहीं था। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनावों में येदियुरप्पा को सांत्वना से संतुष्ट होना पड़ा, हालांकि उन्हें लगा था कि वह प्रथम आए हैं।

अब हालात बदल चुके हैं। कुछ सप्ताह पहले तक कर्नाटक और महाराष्ट्र में खास अंतर नहीं था। दोनों राज्यों में किसी तरह सत्ता चल रही थी। लेकिन फडणवीस फिसल गए जबकि येदियुरप्पा कर्नाटक के मतदाताओं को समझाने में कामयाब रहे कि यह मतदान विधायक (ये कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से भाजपा में आए विधायक थे) के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए हो रहा है।

मुख्यमंत्री कम ही इतनी मेहनत करते नजर आते हैं। वह हर विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन बार गए। उन्होंने कुल 50 यात्राएं कीं।

कर्नाटक में जीत के पीछे क्या वजह रही? यकीनन येदियुरप्पा की मेहनत। मुख्यमंत्री कम ही इतनी मेहनत करते नजर आते हैं। वह हर विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन बार गए। उन्होंने कुल 50 यात्राएं कीं। भाजपा पुराने मैसूर में जीती जो वोक्कालिंगा समुदाय और जनता दल सेक्युलर तथा कांग्रेस का गढ़ है। मांड्या जिले की कृष्ण राजा पेट सीट जहां भाजपा को इससे पहले के चुनावों में 10,000 वोट से ज्यादा नहीं मिले वहां जनता दल सेक्युलर के पूर्व विधायक नारायण गौड़ा इस बार 9,000 से अधिक मतों से जीते। वह उन 17 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा की सरकार बनने की राह आसान की थी। यह जीत दोहरे महत्त्व की है। एक तो यहां चुनाव प्रबंध की कमान येदियुरप्पा के छोटे बेटे विजयेंद्र के हाथ में थी। निवर्तमान कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी क्षेत्र की वरुणा सीट से चुनाव लड़े थे। विजयेंद्र उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने यह सीट बीएल संतोष समर्थित प्रत्याशी को दे दी। कांग्रेस ने सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र को उतारा जो यहां से जीत गए। परंतु आखिरकार केआर पेट सीट छीनकर विजयेंद्र ने अपनी हैसियत दर्ज कराई।

येदियुरप्पा का कार्य क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र शिमोगा है। परंतु वह केआर पेट में पैदा हुए थे। विजयेंद्र ने अपनी नीति में इस बात को शामिल किया। 2 लाख मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में करीब 93,000 वोक्कालिंगा मतदाता हैं। तार्किक रूप से देखें तो लिंगायतों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा के लिए यहां जाति का कार्ड खेलना असंभव था। इसके बजाय विजयेंद्र ने अपने प्रचार में यह छवि पेश की कि वह अपने पिता की जमीन पर वापस आए हैं। लोगों ने कहा कि भाजपा पुराने मैसूर में कभी नहीं जीत सकती। जवाब में विजयेंद्र कहते कि अगर अमित शाह भाजपा को बंगाल में जिता सकते हैं तो भाजपा यहां भी जीत सकती है।

एक बात को बिल्कुल ठीक-ठीक समझने की आवश्यकता है कि कर्नाटक उपचुनावों में भाजपा को जीत मिली, उम्मीदवारों को नहीं। येदियुरप्पा के आलोचक अब अपना ध्यान शासन-प्रशासन की कमियों पर केंद्रित करेंगे लेकिन विजयेंद्र ने भाजपा के लिए एक ऐसी राजनीतिक राह खोली है जो अब तक बंद चली आ रही थी। कर्नाटक के राजनीतिक भविष्य को समझने के लिए विजयेंद्र तथा पार्टी के अन्य युवा नेताओं पर आने वाले दिनों में नजर रखनी होगी।

कानाफूसी

आजाद का दल

एक अरसे तक शांत रहने के बाद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अब अपने नाम से उपनाम रावण हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि वह बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए सक्रिय राजनीति में आएंगे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती आजाद को भाजपा का एजेंट भी कह चुकी हैं। यह बात अलग है कि आजाद ने हमेशा उनका नाम आदर से लिया है। आजाद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है। आजाद लखनऊ में एक रैली करके अपने राजनीतिक दल की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टी का मुख्यालय भी लखनऊ होगा। उनकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा से बसपा, सपा और कांग्रेस के दलित नेताओं के बीच संत्रास उत्पन्न होना लाजिमी है। इससे दलित मतों में जो बंटवारा होगा वह भाजपा के काम अवश्य आ सकता है।

रहस्यमय अनुपस्थिति

राज्य सभा सचिवालय ने गुरुवार को उन 16 सांसदों के नाम जारी किए जो बुधवार को उच्च सदन में नागरिकता संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान अनुपस्थित थे। इनमें शिवसेना के तीनों सांसदों के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के चार में से दो सांसद शामिल थे। राकांपा प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने जहां विधेयक के खिलाफ मतदान किया, वहीं मजीद मेनन और वंदना चव्हाण अनुपस्थित रहे। अन्य अनुपस्थित सांसदों में भाजपा के चुन्नीभाई गोहेल और अनिल बलूनी शमिल हैं। ये दोनों ही अस्वस्थ हैं। सपा के बेनी प्रसाद वर्मा और स्वतंत्र सांसद अमर सिंह भी बीमार होने के कारण शामिल नहीं हो सके। तृणमूल कांग्रेस के के डी सिंह भी अनुपस्थित रहे। परंतु सबसे रहस्यमय अनुपस्थिति थी बसपा के दो सांसदों राजाराम और अशोक सिद्धार्थ की। दिलचस्प बात यह है कि जनता दल (सेक्युलर) के इकलौते सांसद डी कुपेंद्र रेड्डी ने अपनी पार्टी के प्रमुख एच डी देवेगौड़ा की तरह बहस के दौरान विधेयक का विरोध किया लेकिन मतदान के वक्त वह सदन में नजर नहीं आए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के धर्मपुरी श्रीनिवास भी अनुपस्थित रहे जबकि पार्टी के अन्य सांसदों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया।

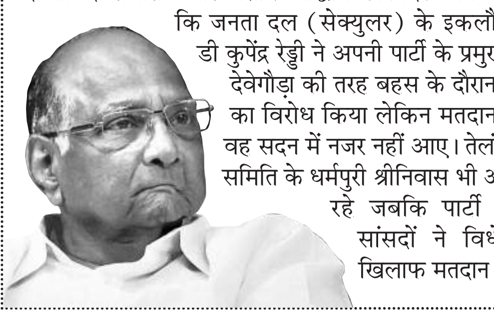

आपका पक्ष

रेबीज संक्रमण के रोकथाम के हों उपाय

हाल में जारी नैशनल हेल्थ प्रोफाइल के आंकड़ों के अनुसार रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण मरने वालों की संख्या इससे संक्रमित होने वालों की संख्या के समान रही है। रेबीज से होने वाली मौत के ये आंकड़े बेहद चिंताजनक है। रेबीज वायरस के वाहक सामान्यत: संक्रमित कुत्ते, घोड़े, बंदर होते हैं जिनके संपर्क में लोग रहते हैं। रेबीज संक्रमण के शिकार होने के सबसे अधिक मामले कुत्ते के काटने के होते हैं। कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाएं उनकी बढ़ती आबादी के कारण हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधित वैश्विक 10 प्रमुख संकट की सूची में रेबीज वायरस द्वारा होने वाले संक्रमण भी शामिल है। इस पर वर्ष 2019 में सभी हितधारकों को फौरन ध्यान देने की जरूरत बताई गई है।

दुनिया भर में 28 सितंबर को विश्व ऐंटी रैबीज दिवस मनाया जाता है। भारत में इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। इसकी रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने होंगे। कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय नसबंदी रहा है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। लेकिन समुचित प्रशिक्षण के अभाव एवं राशि की कमी जैसी बुनियादी समस्याओं के कारण यह अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त दिक्कतों को दूर करना होगा। आबादी वाले क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। रेबीज संक्रमित व्यक्ति के समुचित इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऐंटी रेबीज दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

रेबीज के इलाज के लिए अस्पतालों में ऐंटी रेबीज की दवाई पर्याप्त मात्रा में हो

ऋषभ देव पांडेय, जांजगीर चांपा

रोजगार सृजन के हों ठोस उपाय

पिछले माह एक रिपोर्ट आई थी कि देश में बेरोजगारी दर पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि सरकार ने इस आंकड़े को खारिज कर दिया था। लेकिन देश में बेरोजगारी की समस्या बरकरार है और रोजगार सृजन भी बेरोजगारी को दूर करने में असमर्थ दिखाई पड़ रहा है। हाल में टीमलीज द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में रोजगार के अवसरों में 7.12 प्रतिशत की वृद्धि के आसार दिख रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 क्षेत्रों में से सात में नौकरी गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद है जबकि नौ क्षेत्रों में कमी आने की आशंका है। देश में फिलहाल आर्थिक सुस्ती छाई हुई है। वाहन क्षेत्र में मंदी से कई लोग बेरोजगार भी चुके हैं। वहीं आंकड़ों को देखा जाए तो 19 में केवल सात क्षेत्रों में 7 प्रतिशत की वृद्धि दिख रही है जबकि नौ क्षेत्रों में कमी भी दिखाई पड़ रही है। अत: सरकार को रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

अंकित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

संक्षेप में

नवंबर में वनस्पति तेल आयात मामूली घटा

देश में वनस्पति तेल का आयात नवंबर महीने में मामूली घटकर 11.28 लाख टन रह गया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ने कहा कि गैर खाद्य तेल का आयात घटने से वनस्पति तेल आयात कम रहा है। नवंबर में कुल वनस्पति तेल आयात में खाद्य तेल का आयात बढ़कर 10,97,424 टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान महीने में 10,73,353 टन था। एसईए ने बयान में कहा कि गैर खाद्य तेल आयात हालांकि इस दौरान घटकर 30,796 टन पर आ गया। एक साल पहले यह 60,450 टन था। नवंबर के दौरान वनस्पति तेल आयात 11,28,220 टन रहा, जो नवंबर, 2018 में 11,33,893 टन था। तेल वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक होता है। *भाषा*

वर्ष 2018-19 में 37 लाख टन चीनी का निर्यात

सरकार ने सितंबर को समाप्त विपणन वर्ष 2018-19 में चीनी के अधिशेष स्टॉक का निपटारा करने के लिए लगभग 37 लाख टन चीनी का निर्यात किया। शुक्रवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री दानवे रावसाहेब दादराव ने कहा कि चीनी मिलों को उनके एमआईक्यूएम (न्यूनतम सांकेतिक निर्यात कोटा) आवंटन के अनुसार चीनी निर्यात करने की सलाह दी गई थी। दादराव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, 'देश से अधिशेष चीनी निपटारा करने के लिए, चीनी सत्र 2018-19 (अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019) में निर्यात के लिए मिलवार 50 लाख टन चीनी का एमआईक्यूएम कोटा तय किया गया था।' उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित मात्रा के मुकाबले लगभग 37 लाख टन निर्यात किया गया है। *भाषा*

फसलों पर बारिश-ओलों की मार

अगले 24 घंटे में बारिश का अनुमान, फसलों को और हो सकता है नुकसान

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 13 दिसंबर

उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सरसों और जौ की फसल पर मार पड़ी है। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों को होने की आशंका है। आगे बारिश और होने पर गेहूं की बुआई में और देरी के साथ अन्य रबी फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी तथा मैदानी भागों में बारिश होने का अनुमान है।

किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष और बुलंदशहर के किसान पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि बुलंदशहर जिले के कुछ इलाकों समेत उत्तर भारत के जिन इलाकों में ओले पड़े हैं, वहां गेहूं को नुकसान हुआ है और जहां सिर्फ बारिश हुई है, वहां गेहूं को फायदा हो सकता है।

सिंह बताते हैं कि इस समय सरसों में फूल आ रहे हैं। ऐसे में सरसों उत्पादक इलाकों में ओले पड़ने से इसे काफी नुकसान होने की आशंका है। सरकार को रबी की फसलों को बारिश और ओलों से हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को तत्काल मुआवजा देने का कार्य करना चाहिए। ऐंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा कि बारिश और ओलों की सबसे ज्यादा मार सरसों पर पड़ी है। इसके साथ ही चना, जौ, गेहूं को भी नुकसान की खबर है। जिन इलाकों में गेहूं की बुआई में देरी है, वहां इसकी बुआई और पिछड़ सकती है।

मध्य प्रदेश के भोपाल, देवास, नीमच, और रायसेन आदि जिलों के साथ हरियाणा के नूंह, नगीना, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, पिनगवां आदि जिलों और राजस्थान के नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू आदि जिलों के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की खबर है। इस बीच, राज्य सरकारें किसानों को नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दे रही हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर चिंता जताते हुए कहा कि नुकसान की जांच कराकर किसानों को राहत दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने ट्वीट कर कहा कि आज प्रदेश के बहुत से जिलों से ओलावृष्टि कीखबरें प्राप्त हुई हैं, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किसानों के साथ हर संकट में साथ खड़े है और हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं।

किसानों को मिला आश्वासन

- सबसे ज्यादा सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका
- ओलों से गेहूं को नुकसान, लेकिन बारिश से फायदे की भी संभावना
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नुकसान की जांच कराकर किसानों को राहत देने की बात कही
- मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने ट्वीट कर किसानों को हरसंभव मदद देने का वादा किया

अगले 24 घंटों में बारिश का अनुमान

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ अभी बना हुआ है जो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से विकसित हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पंजाब पर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मध्यम से भारी बारिश और हिमपात जारी रहने की उम्मीद है, जबकि पंजाब, उत्तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होगी।

चार साल के शीर्ष स्तर पर पहुंचा सोयाबीन

सुशील मिश्र
मुंबई, 13 दिसंबर

उत्पादन कम होने के अनुमान से सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। हाजिर और वायदा बाजार में सोयाबीन के दाम करीब चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। मांग में तेजी कीमतों को मजबूती प्रदान कर रही है। चालू फसल सीजन में सोयाबीन उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश और बाढ़ के कारण सोयाबीन की फसल को नुकसान होने से उत्पादन प्रभावित हुआ है।

पिछले तीन महीनों से सोयाबीन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वायदा और हाजिर बाजार में सोयाबीन के दाम 4,300 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गए हैं। इस महीने की शुरुआत में सोयाबीन 4,000 रुपये और नवंबर की शुरुआत में 3,800 रुपये प्रति क्विंटल थी। सितंबर में सोयाबीन के भाव 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे चल रहे थे। सोयाबीन के मौजूदा दाम अप्रैल 2016 के स्तर पर पहुंच गए हैं। कीमतों में तेजी के मद्देनजर सोयाबीन 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच सकती है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2012 में सोयाबीन के दाम 4,910 रुपये प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड बनाया था जो इस बार टूट सकता है।

कृषि मंत्रालय द्वारा चौथे अग्रिम फसल उत्पादन अनुमान में वर्ष 2018-19 में 139 लाख टन का अनुमान लगाया गया था। हालांकि इस अनुमान का खंडन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के सर्वेक्षण में पिछले महीने ही किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में सोयाबीन का कुल उत्पादन 40.107 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले साल की तुलना में 31.1 फीसदी कम है। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी उत्पादन कम होने के आसार हैं। महाराष्ट्र में सोयाबीन का उत्पादन घटकर 36.295 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले साल के मुकाबले 5.70 फीसदी कम है। राजस्थान में इस बार सोयाबीन उत्पादन महज 6.560 लाख टन रहने के आसार हैं जो पिछले साल की अपेक्षा 26.7 फीसदी कम है।

सोपा के मुताबिक चालू फसल सत्र 2019-20 में सोयाबीन का उत्पादन घटकर 89.84 लाख टन रह सकता है जबकि पिछले साल 109.33 लाख टन था। नई फसल की आवक के समय उत्पादक राज्यों में 1.70 लाख टन सोयाबीन का बकाया स्टॉक बचा हुआ था। इस तरह चालू सीजन में सोयाबीन की कुल उपलब्धता 91.54 लाख टन रहने का अनुमान है। देश में उत्पादन कम होने के कारण सोयाबीन का आयात पिछले साल के 1.80 लाख टन से बढ़कर चालू फसल सीजन में 3 टन तक पहुंच सकता है।

बेमौसम बारिश से उत्पादन प्रभावित

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 13	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,755.0	-0.7	1,906.2	-4.1
Copper	6,097.0	3.9	6,467.1	3.1
Nickel	13,810.0	-22.5	14,685.1	-19.9
Lead	1,920.0	-8.3	2,216.9	7.7
Tin	17,185.0	-0.5	18,003.4	-2.1
Zinc	2,229.0	-6.4	2,598.1	-0.9
Gold ($/ounce)	1,471.8*	-1.1	1,654.7	0.4
Silver ($/ounce)	17.0*	-2.8	19.3	-5.3
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	66.6*	9.8	64.4	8.6
Natural Gas ($/mmBtu)	2.3*	-13.0	2.3	-13.6
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	189.0	12.5	304.0	5.8
Maize	184.7*	2.5	328.6	13.7
Sugar	356.1*	8.1	484.3	-0.6
Palm oil	720.0	35.2	1,129.6	29.2
Rubber	1,620.0*	5.6	1,863.9	-4.2
Coffee Robusta	1,447.0*	11.2	1,899.2	-8.4
Cotton	1,490.5	9.7	1,594.8	-3.2

* As on Dec 13, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 70.8& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker | Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	34.2	12534
Oil and Oilseeds	236.5	80875
Spices	0.1	14
Metal(Dec 12)		
Metal- non ferrous	7422.3	59450
Metal- precious	14152.8	484
Oil and gas(Dec 12)		
Gas	2365.8	43139
Oil	13505.7	2854

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	160.0	112639
Grains	121.5	103860
Oil and Oilseeds	944.3	504295
Others	72.6	68045
Pulses	100.3	57575
Spices	64.2	33023

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Natural Gas (Dec 26)	163.3	1.7
Crude Oil (Dec 18)	4200.0	1.1
Crude Oil Mumbai (Dec 18)	4199.0	1.0
Zinc (Dec 31)	182.7	0.8
Cotton (Dec 31)	19200.0	0.7
Zinc Mini (Dec 31)	182.6	0.7
Kapas (Apr 30)	1093.5	0.6
Losers (* % Change)		
Lead Mini (Dec 31)	153.2	-0.4
Lead (Dec 31)	153.2	-0.4
Gold (Feb 05)	37544.0	-0.4
Gold Mini (Jan 03)	37559.0	-0.4
Cardamom (Jan 15)	3039.8	-0.3

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	867.6	1.0
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	2053.0	0.7
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1093.0	0.6
Chana-Bikaner (Dec 20)	4378.0	0.5
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4461.0	0.3
Losers (* % Change)		
Jeera Unjha (Dec 20)	15900.0	-4.1
Guar Seed 10 (Dec 20)	3918.0	-0.8
Coriander-Kota (Dec 20)	7007.0	-0.7
Soyabean Indore (Dec 20)	4202.0	-0.7
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7109.0	-0.6
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4232.0	-0.4
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6182.0	-0.3

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19200.0	2.6
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	3051.1	2.5
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	2.0
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3848.0	1.9
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	43952.0	0.2
Silver Ahm (Mar 05)	43926.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1307.4	-7.3
Alumini-Mumbai (Dec 31)	133.5	-3.4
Aluminium Mum (Dec 31)	133.5	-3.4
Copper Mum (Dec 31)	442.0	-2.2
Lead Mum (Dec 31)	153.2	-1.4
Lead Min Mumbai (Dec 31)	153.2	-1.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6182.0	2.7
Moong-Merta City (Dec 20)	6689.0	0.2
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3204.0	0.1
Barley Jaipur (Dec 20)	2123.5	0.0
Discount over spot price (In %)		
Jeera Unjha (Dec 20)	15900.0	-3.1
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7109.0	-2.4
Soy Bean Indore (Dec 20)	4202.0	-1.2
Maize-Sangli (Dec 20)	2039.0	-0.6
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	737.7	-0.4
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18650.0	-0.4
Coriander-Kota (Dec 20)	7007.0	-0.1

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98 (100)
Aluminium ingots /kg	135 (135)
Brass sheet cutting /kg	319 (319)
Brass utensil scraps/kg	301 (301)
Copper heavy scrap /kg	424 (423)
Copper utensil scraps/kg	400 (398)
Copper wire bar /kg	458 (457)
Lead ingots /kg	157 (155)
Nickel Cathodes /kg	1040 (1035)
Tin slabs /kg	1275 (1290)
Zinc slabs /kg	184 (184)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10742 (10686)
DCH - 32 /Qtl	11473 (11417)
Jaydhar /Qtl	10067 (10067)
Shankar- 6 /Qtl	11276 (11220)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	902 (900)
Castor Comm /10kg	892 (890)
Ricebran oil/10kg	760 (760)
Groundnut oil /10kg	1060 (1050)
Linseed oil /10kg	875 (865)
Karanji /10kg	780 (780)
Palm oil /10kg	812 (803)
Sunflower exp ref /10kg	860 (855)
Sunflower oil exp /10kg	815 (810)
Soyabean ref / 10kg	855 (850)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3270-3590 (3292-3572)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	59.93 (59.18)
Brent Crude (UK)	66.71 (66.28)
Brent Crude (WTI)	59.18 (59.18)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.26 (2.33)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	271.85 (261.85)
Naptha spot /Rs/MT	45170 (45170)
LSHS spot/ M.T.	36150 (36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950 (33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37676 (37778)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	37827 (37930)
Silver.999/ kg	43880 (43730)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18620.65	18716.25
Alumini-Mumbai (M)	1 K	139.25	138.15
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1950.00	1975.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2120.45	2122.75
Brass-Jamnagar (M)	1 K	315.90	315.90
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3000.00	2983.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4231.65	4290.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4212.50	4247.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4276.55	4287.10
Chana Delhi (N)	1 Q	4450.00	4468.80
Chana-Akola (N)	X	4350.00	4450.00
Coriander-Gondal (N)	X	6750.00	6700.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6900.00	6900.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7006.10	7016.30
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2106.30	2118.85
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2034.85	2068.00
Cotton-Kadi (N)	1 B	18546.30	18644.55
CPO-Kandla (M)	10 K	720.60	725.90
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	735.55	740.75
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	876.30	875.60
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1527.60	1526.90
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3433.05	3428.95
Gold Ahm (M)	10 G	37763.00	37691.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30332.00	30274.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3789.00	3778.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7293.20	7283.35
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3931.80	3937.25
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3850.00	3850.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1140.50	1160.80
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	93.75	94.10
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17200.00	17000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16390.90	16408.70
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1017.45	1027.30
Kapas-Rajkot (N)	X	1017.40	1024.55
Lead Mum (M)	1 K	154.25	155.35
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2000.00	2025.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2324.00	2340.00
Maize-Erode (N)	X	2071.50	2090.90
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Maize-Sangli (N)	X	2035.85	2051.15
Moong-Merta City (N)	1 Q	6680.55	6674.40
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4630.15	4694.50
Nickel Mumbai (M)	1 K	1025.00	1030.30
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3178.00	3195.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	355.00	355.60
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35220.00	35566.65
Rape mustards-Patan (I)	20 K	813.00	811.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2036.00	2046.95
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	793.40	800.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	852.70	863.50
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	852.55	855.05
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	872.50	877.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13200.00	13200.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13200.00	13250.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	43640.00	43884.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4205.00	4252.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4090.50	4177.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4279.90	4343.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4244.00	4297.00
Soymeal Indore (N)	1 T	34000.00	34450.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	852.20	862.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27800.00	27800.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28600.00	28600.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	25740.00	25740.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3336.95	3333.35
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3288.75	3295.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3433.35	3435.70
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3260.00	3250.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3129.55	3133.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6054.70	6016.65
Wheat Delhi (N)	1 Q	2250.00	2250.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2150.00	2140.15
Wheat New Indore (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2062.50	2080.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2180.00	2190.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4925.00	4850.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	182.20	183.00

* as on Dec 12, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19280, 19280, 19150, 19200	2041	319	8002
Jan 31	19430, 19430, 19320, 19350	931	150	3593
Feb 28	19510, 19510, 19460, 19480	13	3	302
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2061, 2079, 2030, 2053	8080	426	19190
Jan 20	2052, 2085, 2030, 2059	53610	3299	59180
Feb 20	2093, 2102, 2053, 2078	7540	671	27350
Mar 20	2118, 2118, 2075, 2095	780	73	2720
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1095.5, 1096.5, 1092, 1093.5	68	16	604
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1096, 1097.5, 1091.5, 1093	724	407	4179
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	3960, 3966, 3906, 3918	4335	493	10730
Jan 20	4002, 4026, 3962, 3972	24405	2940	82235
Feb 20	4052, 4064, 4010, 4018	1720	256	4385
Mar 20	4054, 4054, 4054, 4054	5	1	60
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4260, 4280, 4170, 4232	3760	419	16565
Jan 20	4290, 4326, 4202, 4266	7060	970	27565
Feb 20	4316, 4318, 4214, 4262	440	72	4000
Mar 20	4270, 4270, 4180, 4260	425	41	4270
Apr 20	4200, 4200, 4200, 4200	10	2	20
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	736, 737, 722.9, 726.8	15050	1031	29100
Jan 31	739.8, 739.8, 727, 729.9	10430	713	45920
Feb 28	734.3, 736.5, 727.7, 729.9	3610	190	5520
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1304.1, 1311.9, 1302.2, 1307.4	155.88	364	272.52
Jan 31	1316.7, 1321, 1315.6, 1316.8	23.4	49	61.92
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4474, 4482, 4450, 4461	2360	158	4200
Jan 20	4488, 4499, 4468, 4474	13650	985	15580
Feb 20	4455, 4455, 4424, 4451	1160	30	1200
Apr 20	4360, 4380, 4360, 4361	130	12	2040
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	864.4, 872.4, 864.4, 867.6	5035	427	10485
Jan 20	865.8, 874.6, 865.2, 867.4	25745	2579	46560
Feb 20	867, 870, 859, 860.8	4065	387	22155
Mar 20	865, 865, 860.2, 860.2	70	8	80
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4262, 4296, 4182, 4202	9035	1161	14900
Jan 20	4276, 4330, 4188, 4208	84495	9154	183250
Feb 20	4320, 4360, 4212, 4236	21390	3097	114130
Mar 20	4350, 4378, 4250, 4270	4905	722	35380
Apr 20	4362, 4386, 4286, 4324	365	72	1885
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7166, 7203, 7095, 7109	1415	154	2395
Jan 20	7268, 7290, 7166, 7183	7555	1183	61735
Feb 20	7371, 7385, 7272, 7294	1065	158	3805
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4367, 4380, 4350, 4378	5420	307	7220
Jan 20	4369, 4395, 4353, 4387	16610	1262	46490
Mar 20	4338, 4344, 4321, 4340	890	80	3220
Apr 20	4320, 4320, 4320, 4320	10	1	560
May 20	4340, 4340, 4340, 4340	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3030, 3050, 3029, 3039.8	0.4	4	11.9
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	7050, 7050, 6960, 7007	820	54	3850
Jan 20	6650, 6700, 6510, 6540	1910	175	8100
Apr 20	6950, 6950, 6825, 6846	520	51	4080
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	16700, 16785, 15900, 15900	447	70	87
Jan 20	15880, 15970, 15755, 15815	756	243	2895
Mar 20	15875, 15930, 15765, 15810	72	24	189
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6184, 6322, 6096, 6182	490	84	4460
Mar 20	6240, 6308, 6160, 6184	2415	448	6980
Apr 20	6210, 6210, 6110, 6164	610	114	2340

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.75, 134.25, 133.65, 133.75	3585	597	7650
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.65, 134.15, 133.6, 133.75	1726	1295	2926
Jan 31	134, 134.45, 133.95, 134.1	89	86	735
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	442.8, 444.95, 442.8, 444.05	17090	5450	15372.5
Jan 31	448.25, 449.35, 447.9, 448.7	785	292	1820
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.4, 153.95, 153.4, 153.85	6215	1008	4825
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.4, 153.9, 153.4, 153.8	2341	1955	2074
Jan 31	152.75, 153.1, 152.75, 152.95	85	78	862
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1020.7, 1032.4, 1020.7, 1030.1	8808	5358	2893.5
Jan 31	1017.4, 1027, 1017.4, 1024.5	213	139	372
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.1, 184.05, 183.1, 183.65	19320	3133	15860
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182.85, 183.75, 182.85, 183.4	5498	4390	6148
Jan 31	180.6, 181.25, 180.6, 180.85	897	548	6953
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37466, 37730, 37466, 37696	6.85	5790	16.08
Apr 03	37619, 37784, 37530, 37748	0.22	211	2.72
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30416, 30455, 30408, 30419	0	122	0
Jan 31	30356, 30397, 30101, 30302	0	85	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37512, 37700, 37400, 37677	0.81	6765	0.84
Feb 05	37501, 37727, 37475, 37700	0.18	1499	0.26
Mar 05	37561, 37722, 37561, 37702	0.01	53	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3846, 3851, 3826, 3840	0.01	1183	0.01
Jan 31	3828, 3830, 3816, 3823	0	268	0
Feb 28	3820, 3820, 3818, 3819	0	3	0
Mar 31	3839, 3839, 3839, 3839	0	1	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	43908, 44292, 43880, 44255	269.88	7536	374.46
May 05	44610, 44751, 44600, 44738	0.78	26	6.21
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	43970, 44300, 43907, 44268	24.34	16737	31.58
Apr 30	44442, 44900, 44419, 44734	1.77	1160	1.76
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	43855, 44300, 43710, 44264	81.74	12916	57.45
Apr 30	44443, 44788, 44440, 44751	1.18	221	1.87

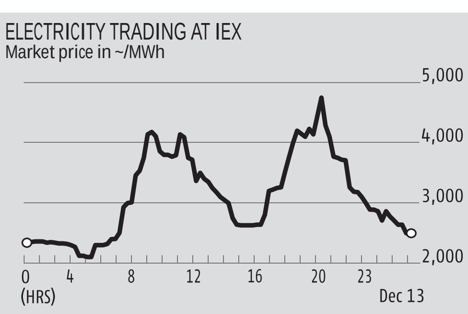

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	164.1, 165.1, 159.8, 160.7	65785mb	27528	37300mb
Jan 28	164.8, 165.3, 160.2, 160.8	6421mb	3229	13163mb
Feb 25	162.7, 163.1, 158.5, 158.7	670mb	524	3211mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4196, 4250, 4194, 4242	8238bl	40297	3301bl
Jan 17	4200, 4247, 4194, 4242	574bl	3146	476bl
Feb 19	4219, 4219, 4219, 4219	1bl	1	1bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4198, 4248, 4192, 4241	1643bl	68605	740bl

सायं सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19020, 19300, 18950, 19230	2432	430	8546
Jan 31	19150, 19450, 19100, 19380	816	151	3457
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1081, 1096.5, 1079.5, 1095	320	67	604
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1080, 1097.5, 1079.5, 1095	1287	622	4090
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	718, 732.8, 717.3, 731.4	12180	897	31130
Jan 31	719.9, 734.6, 718, 733.3	13130	841	44930
Feb 28	715.5, 731.5, 715.5, 730.6	1720	135	3800
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	854, 863, 851.6, 861.4	6610	452	13085
Jan 20	855.6, 865.6, 852.6, 864.4	28135	2629	50310
Feb 20	851.2, 862, 850, 860.6	4660	331	21110

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	132.5, 133.7, 132.4, 133.5	9155	1343	7560
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	132.5, 133.8, 132.3, 133.45	3763	3079	2738
Jan 31	132.7, 133.9, 132.7, 133.75	292	238	711
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	441.8, 442.95, 439, 441.95	36375	12336	13125
Jan 31	446.85, 447.2, 443.5, 446.4	902.5	351	1532.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.8, 154.2, 153.05, 153.2	16295	2787	4460
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.65, 154.15, 153.1, 153.2	6538	5492	1858
Jan 31	153.15, 153.2, 152.4, 152.55	266	224	839
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1015.4, 1024.9, 1005, 1020.7	35953.5	21456	1701
Jan 31	1012.1, 1019, 1001.6, 1014.8	870	565	340.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	181.9, 183.7, 181.65, 182.7	57835	9248	12845
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	181.65, 183.4, 181.65, 182.55	21088	15498	4956
Jan 31	180, 180.65, 179.3, 180.25	3437	1973	6737
Feb 28	180.1, 180.1, 179.8, 180	3	3	12
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37770, 38068, 37470, 37544	19.75	16289	15.53
Apr 03	37812, 38130, 37564, 37614	0.42	347	2.6
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30585, 30595, 30360, 30405	0.01	501	0
Jan 31	30474, 30560, 30350, 30375	0	121	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37749, 38044, 37500, 37559	2.26	19129	0.79
Feb 05	37763, 38070, 37504, 37561	0.61	4691	0.25
Mar 05	37790, 38092, 37555, 37621	0.01	57	0
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3856, 3880, 3845, 3848	0.01	1651	0.01
Jan 31	3830, 3857, 3820, 3826	0	523	0
Feb 28	3744, 3842, 3744, 3810	0	12	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	43969, 44630, 43703, 43926	883.83	23920	372.27
May 05	44555, 45099, 44287, 44504	2.16	70	5.85
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	43900, 44644, 43747, 43952	83.44	55445	31.02
Apr 30	44488, 45125, 44250, 44441	4.83	3430	1.59
Jun 30	45200, 45400, 45200, 45300	0	2	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	43910, 44639, 43722, 43943	256.83	38692	52.29
Apr 30	44525, 45110, 44239, 44468	4.35	794	1.62

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	160, 164.2, 159.2, 163.3	136065mb	57913	28630mb
Jan 28	160.7, 164.7, 160, 163.8	9221mb	4884	11551mb
Feb 25	158.7, 162.2, 158.4, 161.8	964mb	701	2958mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4161, 4223, 4152, 4200	25702bl	126359	2064bl
Jan 17	4166, 4224, 4158, 4201	1011bl	7578	361bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4153, 4225, 4153, 4199	5555bl	219720	429bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

मोदी-आबे की गुवाहाटी शिखर वार्ता रद्द

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा से पहले एक जापानी दल ने गुवाहाटी जाकर वहां की स्थिति का लिया था जायजा

अर्चिस मोहन

गुवाहाटी में बिगड़ते सुरक्षा हालात के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की यहां होने वाली वार्षिक शिखर वार्ता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। आबे को 15 से 17 दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत आने की योजना थी। बुधवार को संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक बहुमत से पारित होने के बाद गुरुवार से ही असम की राजधानी गुवाहाटी सहित पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। सिर्फ आबे की ही गुवाहाटी यात्रा रद्द नहीं हुई है बल्कि विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। शाह को रविवार को शिलॉन्ग के नजदीक नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेना था और अगले दिन तवांग के एक महोत्सव में भी शिरकत करना था। गृह मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने भी इस क्षेत्र में अपना दौरा रद्द कर दिया है। यह यात्रा 18 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान होनी थी।

देश के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक भारत और जापान दोनों ही पक्षों ने फिलहाल इसे टालने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने निर्णय के लिए कोई वजह बताए बगैर कहा कि भारत और जापान दोनों ने 15-17 दिसंबर को शिखर वार्ता के लिए आबे के दौरे को आगे किसी अनुकूल तारीख तक टालने का फैसला किया है। जापानी प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने से पहले गुरुवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमिन और गृहमंत्री असदुज्जामान खान ने भी विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी।

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग फोटो: दलीप कुमार

रणनीतिक सूत्रों का कहना है कि जापानी सरकार ने भारत को यह सूचित कर दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच आबे की गुवाहाटी यात्रा संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब यह शिखर वार्ता अगले साल हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि वैकल्पिक स्थान पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि शीर्ष नेताओं की शिखर वार्ता की मेजबानी करने में काफी तैयारी करनी पड़ती है।

शिखर सम्मेलन भारत और जापान में बारी-बारी से होता है। बुधवार को जापान की एक टीम ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुवाहाटी का दौरा किया था जिसके बाद जापान ने भारत को सूचित कर दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में आबे की यात्रा संभव नहीं है।

विवादास्पद कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। असम के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है जबकि सेना ने प्रदर्शन और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कई जिलों में फ्लैग मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने पिछले दो दिनों में कई गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी।

पिछले पांच सालों में मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी से इतर दूसरे शहरों में उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक कराने की कोशिश की है और गुवाहाटी का चयन भी इसका ही नतीजा था। अपनी पहले की यात्रा के दौरान आबे अहमदाबाद और वाराणसी गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी भी अहमदाबाद और चेन्नई में की गई थी। हाल के वर्षों में जापान ने असम में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों में निवेश किया है। जापान के प्रधानमंत्री मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए जापानी सैनिकों के स्मारक का दौरा भी करने वाले थे।

हालात से और मजबूत होंगे सैम्यूल जिरवा

ऋत्विक शर्मा

संसद के दोनों सदनों ने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया जिसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आबादी के एक हिस्से में रोष बढ़ गया है और खासतौर पर उस क्षेत्र में छात्रों का विरोध प्रदर्शन ज्यादा देखा जा रहा है जहां सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों की तादाद (25 में से 18) अच्छी खासी है। इस विरोध प्रदर्शन की वजह यह भी है कि विपक्ष में कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जो उनकी चिंताओं को आवाज दे सके। ज्यादातर विरोध प्रदर्शन बिखरे हुए हैं और इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कोई भी नहीं कर रहा है। यहां की मूल आबादी की यह चिंता बढ़ने लगी है कि आप्रवासी कहीं उनकी जमीन पर कब्जा न कर लें। और इसी डर की वजह से वे बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर रहे हैं। इन समूहों में से नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) विरोध प्रदर्शन की एक प्रमुख कड़ी के तौर पर उभरा है जिसकी शुरुआत तब हुई जब इस विधेयक को जुलाई 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था।

एनईएसओ की कमान सैम्यूल जिरवा के हाथों में है। मेघालय के शिलॉन्ग में सेंट एंटनी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय से स्नातक करने वाले 45 साल के जिरवा करीब तीन दशकों से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। वह साल 2002 से 2012 के दौरान खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) के अध्यक्ष भी रहे। इस अवधि के दौरान वह एनईएसओ के प्रचार सचिव भी रहे हैं। वर्ष 2012 में उन्हें एनईएसओ का अध्यक्ष चुना गया।

जिरवा एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार थे। केएसयू से अलग होने के बाद उन्होंने शादी की और उनकी एक तीन साल की बेटी है। केएसयू का गठन 1978 में हुआ था और वह खासी समुदाय के लिए छात्र राजनीति के प्रभाव का गवाह रहे हैं। उनकी परवरिश एक ऐसे परिवार में जिसमें सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे। उनके पिता अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में थे जबकि उनकी मां स्वास्थ्य विभाग में थीं। वह कहते हैं, 'हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि कैसे केएसयू ने हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए कोशिश की।'

चित्रांकन : विनय सिन्हा

इस छात्र संगठन की एक सबसे बड़ी चिंता यह रही है कि यहां बांग्लादेश के लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसके अलावा इस संगठन का जोर छात्रों के कल्याण, शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और सामुदायिक स्वास्थ्य पर रहा है। 1980 के दशक से ही केएसयू खासी पहाड़ियों में यूरेनियम के खनन के प्रस्ताव का पूरी सक्रियता से विरोध करती रही है।

नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स समन्वय समिति का गठन 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ था जिसका नाम 1993 में एनईएसओ हो गया। यह सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के शीर्ष छात्र संगठन का समन्वय करने वाली एक संस्था है। इसके आठ सदस्यों में से दो मेघालय से हैं जिनमें गारो छात्र संगठन भी शामिल है। बाकी में नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन और मिजो जिरलाई पॉल शामिल हैं। इनमें से हरेक छात्र संगठन अपने एक सदस्य का मनोनयन एनईएसओ में प्रतिनिधित्व के तौर पर करता है। जिरवा कहते हैं, 'एनईएसओ जमीनी स्तर पर एक प्रमुख संगठन के तौर पर काम करता है। हम नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ एक ठोस आवाज के तौर पर उभरने में सफल रहे हैं भले ही भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों को अनुसूची छह वाले क्षेत्रों को छूट देने और इनर लाइन परमिट वाले राज्यों के आधार पर बांटने की कोशिश की है और मणिपुर में आईएलपी लागू कर दिया है।' अनुसूची छह के तहत पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों का स्वायत्त प्रशासन आता है। वहीं इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है ताकि वे किसी संरक्षित क्षेत्र में किसी खास अवधि के लिए यात्रा कर सकें।

2016 में संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किए जाने के बाद उस इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया तब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और एनईएसओ के नेताओं ने इस बाबत मुलाकात की। समिति ने इस साल जनवरी में संसद में एक रिपोर्ट जमा की। इसके बाद ही पूर्वोत्तर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे, हालांकि उस वक्त प्रदर्शन बहुत उग्र नहीं था। राज्यसभा में पारित न होने की वजह से यह विधेयक रद्द हो गया। धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का विधेयक में प्रावधान किया गया है। जिरवा कहते हैं, 'कल को दूसरे देशों के लोग भी आ सकते हैं और वे आसानी से कह सकते हैं कि वे 10 साल पहले आए। जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है उनके बारे में आप यह कैसे कह सकते हैं कि वे आज बाहर से आए हैं या 20 साल पहले आए हैं?'

प्रदर्शनों के दौरान हिंसा होने पर अफसोस जताते हुए वह कहते हैं कि विधेयक पर विरोध जताने के लिए संसद में इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों का पूरा समर्थन नहीं मिला। वह कहते हैं, 'यह दुख की बात है कि हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि भी अपने गठबंधन की तर्ज पर ही चलते हैं। जो लोग भाजपा के सहयोगी हैं उन्होंने इस विधेयक पर सरकार का समर्थन कर दिया, बिना यह सोचे कि इससे उनके लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य पर असर पड़ेगा या नहीं। इसी वजह से लोग भड़के हुए हैं और सड़कों पर उतर आए हैं।' उन्होंने अपना मन बना लिया है। वे संघ के एजेंडा को बढ़ाना चाहते हैं।' उनका कहना है कि एनईएसओ उच्चतम न्यायालय में भी जाएगा क्योंकि वहीं से न्याय मिलने की थोड़ी उम्मीद बची है।

1991 में छात्र राजनीति से जुड़े जिरवा क्या मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ेंगे? वह कहते हैं, 'पूर्वोत्तर के छात्र संगठन सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं जैसा कि भारत के अन्य हिस्से में होता है। लेकिन यहां छात्र संगठन नस्लीय आधार पर आधारित है।' उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ छात्र नेता सक्रिय राजनीति से जुड़ सकते हैं। लेकिन वह अपने बारे में इस तरह की कयासों से इनकार करते हैं। हालांकि वह यह भी कहते हैं, 'अगर हालात की ऐसी मांग होगी तब हम भी राजनीति से जुड़ सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि क्या करना है।'

ब्रिटेन में जॉनसन को मिली ऐतिहासिक जीत

बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी को 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में 365 सीटों पर जीत मिली है जो बहुमत से 79 सीटें अधिक है

ब्रिटेन में हुए ऐतिहासिक चुनाव में मतदाताओं ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को शक्तिशाली नया जनादेश दिया है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को शुक्रवार को संसद में निर्णायक बहुमत मिला ताकि वह अगले महीने यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन के अलग होने के करार (ब्रेक्जिट) को अंतिम रूप दे सकें।

55 वर्षीय जॉनसन ने 1980 में मार्गरेट थैचर के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत दिलाया है। जीत के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने के लिए दिन-रात काम करेंगे। ब्रिटिश संसद के 650 सदस्यीय निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत से 79 सीटें अधिक है। ब्रिटेन में दशकों बाद शीत ऋतु में हुए मतदान में 67 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपनी विजयी रैली को संबोधित करते हुए जॉनसन ने इसे ब्रेक्जिट को लेकर जारी गतिरोध के लिए नई सुबह करार दिया और दावा किया कि वह मतदाताओं की ओर से जताए गए पवित्र विश्वास को खंडित नहीं होने देंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने कहा कि मजबूत नया जनादेश 31 जनवरी को 28 सदस्यीय आर्थिक समूह यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने के रास्ते पर बढ़ने के लिए मिला है।

माना जा रहा है कि ब्रेक्जिट के मुद्दे पर लंबे समय से जारी गतिरोध से परेशान होकर मतदाताओं ने जॉनसन को विशाल जनादेश दिया है ताकि जनवरी तक वह ब्रिटेन को ईयू से अलग कर सकें और कोई अगर-मगर नहीं रहे। इस चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी को केवल 203 सीटें मिली यह 1935 के बाद लेबर पार्टी की सबसे करारी हार है। पांच साल में तीसरी बार और 2016 में यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर जनमत संग्रह होने के बाद दूसरी बार ब्रिटेन में आम चुनाव हुए हैं। इस साल के शुरुआत में थेरेसा मे से सत्ता लेने वाले जॉनसन ने 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट की समयसीमा तय की थी, लेकिन हाउस ऑफ कॉमंस में बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें बाधा का सामना करना पड़ा।

मोदी और ट्रंप ने दी बधाई

जॉनसन के भारी बहुमत से दोबारा निर्वाचित होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। मोदी ने ट्वीट किया, 'मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भारत-ब्रिटेन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए मिलकर काम करने को इच्छुक हूं।' अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जॉनसन को बधाई देते हुए कहा कि दोनों देश अब नया व्यापार समझौता करने के लिए मुक्त हैं। जॉनसन ने अमेरिकी व्यापार समझौते को ब्रिटेन को यूरोपीय संघ छोड़ने के उपहार के तौर पर पेश किया है जबकि लेबर पार्टी का दावा है कि यह ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल देगा। वहीं जॉनसन की जीत पर रूस ने कहा कि वह हमेशा उम्मीद करता है कि चुनाव में उन शक्तियों को आवाज मिलेगी जो अच्छे संबंध के हिमायती हैं लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर निश्चित नहीं है। एजेंसियां

पृष्ठ-1 का शेष

पूर्वोत्तर में रिफाइनरी क्षेत्र में बढ़ा संकट

नुमालीगढ़ रिफाइनरी के प्रबंध निदेशक एस के बरुआ ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि रिफाइनरी को यूरो-6 मानकों के अनुरूप उन्नत करने के लिए इसे 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक के लिए योजनाबद्ध ढंग से बंद किया गया था। बरुआ ने कहा, 'हमारे कर्मचारी प्रदर्शनों के चलते रिफाइनरी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।' वहीं इंडियन ऑयल की रिफाइनरी गुवाहाटी, डिगबोई और बोंगाईगांव में हैं। इन रिफाइनरियों में भी उत्पादन नीचे आ गया है। दरअसल जगह-जगह रास्ते अवरुद्ध होने से टैंकर तेल लेकर जा नहीं पा रहे हैं लिहाजा कंपनी ने उत्पादन कम कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा, 'हमारे भंडारण टैंक भरे हुए हैं। टैंकरों की आवाजाही शुरू नहीं होने तक हम तेल का भंडारण कहां करेंगे?'

तेल एवं गैस उत्पादन रुकने से अन्य क्षेत्रों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस बात की भी आशंका है कि असम गैस कंपनी से होने वाली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसा होने पर राज्य भर के 400 से भी अधिक चाय बागानों को होने वाली गैस आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा इलाके में रसोई गैस की आपूर्ति पर भी असर देखने को मिल सकता है। बरुआ कहते हैं, 'पहले से ही रसोई गैस का 10-15 दिनों का बैकलॉग है। प्रदर्शन के दौरान गैस सिलिंडरों का परिवहन मुश्किल होने से इसका असर रसोईघर पर भी देखने को मिल सकता है।' अगर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के हल्दिया से एलपीजी का परिवहन भी प्रभावित होता है तो फिर आने वाले दिनों में बैकलॉग और बढ़ सकता है। समूचे पूर्वोत्तर भारत में आपूर्ति करने वाले थोक बाजार भी प्रदर्शनों के दौरान चार दिनों से बंद चल रहे हैं। असम चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव शिशिर देव कलिता कहते हैं, 'दैनिक आधार पर इन आठ बड़े बाजारों में से हरेक को रोजाना 8-10 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यहां पर प्याज के भाव 180-200 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं।' गुवाहाटी, तिनसुकिया, जोरहाट और डिब्रूगढ़ जिलों में कर्फ्यू लगे होने और सेना के फ्लैग मार्च के बावजूद प्रदर्शनकारी नए नागरिकता कानून के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। शुक्रवार को भी असम में कई जगहों पर राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए गए।

दुनिया की ताकतवर महिलाओं में सीतारमण

फोर्ब्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ और कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ को दुनिया की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं में रखा है।

दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की 2019 की फोर्ब्स सूची में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरे स्थान पर अमेरिकी संसद में निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी हैं। इस सूची में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 29वें स्थान पर हैं।

फोर्ब्स का कहना है कि 2019 में दुनिया भर में महिलाओं से सक्रियता से आगे बढ़कर सरकार, उद्योगों, मीडिया और परमार्थ कार्यों में नेतृत्वकारी भूमिका संभाली। सीतारमण फोर्ब्स की सूची में पहली बार शामिल हुई हैं और वह 34वें स्थान पर हैं। भारत की पहली वित्त मंत्री सीतारमण पहले रक्षा मंत्री भी चुकी हैं। सीतारमण पहली महिला मंत्री हैं जो स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। इससे पहले वित्त मंत्रालय का प्रभार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास रह चुका है। मल्होत्रा सूची में 54वें स्थान पर हैं। एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ होने के नाते वह 8.9 अरब डॉलर की कंपनी में सभी रणनीतिक फैसले लेने के लिए जिम्मेदार हैं। मल्होत्रा कंपनी की सीएसआर समिति की अध्यक्ष और शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। वहीं सूची में 65वें स्थान पर शामिल शॉ भारत की ऐसी सबसे अमीर महिला हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति स्वयं कमाई है। एजेंसियां

फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में पहली बार शामिल हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 34वें स्थान पर रहीं

राहुल के बयान पर घमासान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के झारखंड में बलात्कार पर की गई टिप्पणी को लेकर शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष ने जमकर विरोध जताया और उनसे माफी की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राहुलके बयान की निंदा की और कहा कि यह शर्म की बात है कि कांग्रेस नेता महिलाओं की गरिमा को भूलकर बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस नेता के खिलाफ बलात्कार को लेकर उनकी टिप्पणी के लिए कठोरतम कार्रवाई की मांग की। ईरानी ने गांधी पर आरोप लगाया कि वह झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलात्कार का इस्तेमाल एक राजनीतिक अस्त्र के तौर पर कर रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को झारखंड में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' का वायदा किया था लेकिन जहां भी आप देखते हैं, अब आप 'रेप इन इंडिया' पाते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने सामान्य सा बयान दिया है और उसके लिए उनके माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। थरूर ने कहा कि यह नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से लोगों का ध्यान हटाने की भाजपा की तिकड़म है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूरा पूर्वोत्तर जल रहा है। भाषा